राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय
दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण रविवार 13 सितंबर 2026 वर्ष-9,अंक-222 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

पीएम मोदी का आह्वान-ग्लोबल साउथ आज वैश्विक संकटों की फ्रंट रो में है, लेकिन डिसीजन में बैक रो में

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आधिकारिक आगाज

नई दिल्ली ।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आधिकारिक आगाज शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन संबोधन के साथ हुआ। पीएम मोदी ने अपने भाषण में ग्लोबल साउथ के देशों की मौजूदा स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा, वे वैश्विक संकटों की अग्रिम पंक्ति में हैं, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में पीछे हैं। उन्होंने ब्रिक्स देशों से वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में ब्रिक्स प्रतिनिधियों का स्वागत कर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन-केंद्रित और मानवता-प्रथम दृष्टिकोण पर आधारित है। उन्होंने लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता को भारत की प्राथमिकताएं बताया। इन प्राथमिकताओं के तहत 350 से अधिक बैठकों का आयोजन हुआ और करीब 30 शहरों में प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने भारत की अध्यक्षता को सफल बनाने में मिले सक्रिय सहयोग के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स के संस्थागत कामकाज में निरंतरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया, भले ही इसकी अध्यक्षता हर साल बदलती है। उन्होंने एक ऐसा तंत्र बनाने का प्रस्ताव रखा जिसके तहत ट्रोइका व्यवस्था के जरिए सभी पहलों और नतीजों पर आगे की कार्रवाई हो सके। इसके साथ ही, उन्होंने हर फैसले से जुड़े नोडल पॉइंट, समय-सीमा और कार्यान्वयन की स्थिति को दर्ज करने के लिए एक सुरक्षित डिजिटल रिपॉजिटरी बनाने का सुझाव दिया। अपने संबोधन में, पीएम मोदी ने कहा कि हमें ब्रिक्स को मजबूत करते हुए वैश्विक सुधार की दिशा भी तय करनी होगी। उन्होंने मौजूदा वैश्विक शासन संरचना की तुलना एक पिरामिड से की, जिसके ऊपरी भाग में शक्ति और निर्णय लेने का अधिकार केंद्रित है, जबकि निचले भाग में वे देश हैं जो इन निर्णयों से प्रभावित होते हैं लेकिन उन्हें आकार नहीं दे पाते।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ग्लोबल साउथ आज वैश्विक संकटों की फ्रंट रो में है, लेकिन डिसीजन मेकिंग की बैक रो में है। इस स्थिति को बदलने के लिए, पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों से मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रस्तावों की रूपरेखा तैयार करने का आह्वान किया, जिसे अगले शिखर सम्मेलन तक एक ब्रिक्स रिफॉर्म रोडमैप का रूप दिया जा सके। इस रोडमैप को बनाने में तीन मुख्य पहलुओं - प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम-निर्माण का ध्यान रखने की बात कही गई। प्रतिनिधित्व के संबंध में, पीएम मोदी ने संयुक्त

राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को अब और टाला न जा सकने वाला मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि इस विषय पर टेक्स्ट-आधारित बातचीत को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा।

चुनाव हारने के बाद सरकारी नौकरी में वापसी नहीं

राजस्थान हाईकोर्ट ने केट का फैसला रखा बरकरार, चुनाव लड़ने के लिए स्वेच्छा से इस्तीफा देने वाले कर्मचारी की याचिका खारिज

जयपुर।

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के चुनाव लड़ने से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि नौकरी से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने वाला सरकारी कर्मचारी यदि चुनाव हार जाता है, तो वह दोबारा सरकारी सेवा में बहाली का दावा नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि चुनाव में हार जाना इस्तीफा वापस लेने के लिए नियमों में निर्धारित बाध्यकारी कारण या परिस्थितियों में ऐसा बदलाव नहीं है, जिसके आधार पर इस्तीफा वापस लिया जा सके। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने नीरज बिश्नोई की याचिका खारिज करते हुए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (केट), जयपुर के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने चुनाव लड़ने के उद्देश्य से अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया था और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी लड़ा। ऐसे में चुनाव में हार के बाद अपने निर्णय से पीछे हटकर सेवा में वापसी का अधिकार नहीं बनता। चुनाव लड़ने के लिए दिया था इस्तीफा नीरज बिश्नोई नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में सीनियर ऑडिटर के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 10 अक्टूबर 2023 को इस्तीफा दिया था, जिसे विभाग ने 1 नवंबर 2023 से स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने चूरू जिले की रतनगढ़ विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनाव परिणाम आने के बाद बिश्नोई ने 1 जनवरी 2024 को इस्तीफा वापस लेने और सरकारी सेवा में बहाल करने के लिए आवेदन दिया। विभाग ने 29 जनवरी को उनका अनुरोध खारिज कर दिया। इसके बाद उनका अभ्यावेदन भी 22 फरवरी 2024 को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने केट का रुख किया और वहां से राहत नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

पेंशन और रिटायरमेंट लाभ का दिया तर्क याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इस्तीफा वापस लेने के लिए आवेदन नियमों में निर्धारित 90 दिन की अवधि के भीतर किया गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस्तीफा देते समय उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि इससे पेंशन और अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर असर पड़ेगा।

भारत की धरती से पुतिन ने खींची रेड लाइन, अमेरिका-यूरोप को चेताया

नई दिल्ली।

नई दिल्ली से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूरे यूरोप को एक सीधा और सख्त संदेश दिया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे पुतिन ने कहा कि अगर यूरोपीय देश यूक्रेन की जमीन पर अपने सैनिक भेजते हैं, तो रूस इसे सीधे अपने खिलाफ युद्ध मानेगा। पुतिन ने अपने इस बयान के जरिए अमेरिका, ब्रिटेन और पूरे नाटो को सीधी धमकी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूक्रेन में सैनिकों की संभावित मौजूदगी को रूस सिर्फ मदद या शांति मिशन के तौर पर नहीं देखेगा, बल्कि इसे युद्ध की सीधी कार्रवाई माना जाएगा। रूस पहले भी कई बार साफ कर चुका है कि यूक्रेन में पश्चिमी सैनिकों की तैनाती उसकी सबसे बड़ी 'रेड लाइन' होगी, हालांकि यूरोपीय देशों में अभी तक ऐसी कोई सैन्य तैनाती नहीं हुई है, केवल भविष्य में शांति समझौते के बाद सैनिक भेजने को लेकर चर्चा हुई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली में थे, जहां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। ब्रिक्स में शामिल होने पहुंचे पुतिन ने यूरोपीय देशों की यूक्रेन में संभावित सैन्य तैनाती को लेकर बेहद कड़ा बयान दिया। रूसी मीडिया के मुताबिक, पुतिन ने यूरोपीय नेताओं पर आरोप लगाया कि वे अपने लोगों को रूस के नाम पर डराते हैं, जबकि रूस यूरोपीय देशों के लिए कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि मॉस्को का उनसे संघर्ष शुरू करने का कोई इरादा नहीं है और रूस की तरफ से यूरोप पर हमले का कोई खतरा न तो मौजूद है और न पहले कभी था। इस प्रकार, भारत से पुतिन का संदेश दो हिस्सों में था- रूस यूरोप से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर यूरोपीय सैनिक यूक्रेन की जमीन पर उतरे तो मॉस्को इसे रूस के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई मानेगा।

1 दिन में 20 लाख रेलवे टिकट बुक करने का रिकॉर्ड

नई दिल्ली ।

भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग व्यवस्था ने नया रिकॉर्ड बनाया है। एक ही दिन में करीब 20 लाख रेलवे टिकटों की बुकिंग दर्ज की गई है । त्योहारों और छुट्टियों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या के बीच यह आंकड़ा रेलवे की डिजिटल टिकटिंग व्यवस्था के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है। बड़ी संख्या में यात्रियों ने घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक किए। रेलवे लगातार अपनी ऑनलाइन सेवाओं की क्षमता बढ़ाने और यात्रियों को सुविधाजनक टिकट बुकिंग उपलब्ध कराने पर जोर दे रहा है। रिकॉर्ड बुकिंग के दौरान सर्वर पर बढ़े दबाव को संभालना भी रेलवे के लिए महत्वपूर्ण चुनौती रहा।

शी जिनपिंग भारत पहुंचे, आज पीएम मोदी से होगी अहम बैठक

गलवान झड़प के बाद पहली भारत यात्रा, ब्रिक्स सम्मेलन में द्विपक्षीय संबंधों और सीमा पर शांति पर होगी चर्चा

नई दिल्ली।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए शनिवार को भारत पहुंचे हैं। उनका विमान दोपहर करीब 12 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा। लगभग सात साल बाद शी जिनपिंग की यह पहली भारत यात्रा है। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद उनका भारत दौरा दोनों देशों के रिश्तों में जारी सुधार की प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। शी का भारत दौरा ऐसे समय में हुआ है, जब भारत और चीन 2020 की गलवान झड़पों के बाद द्विपक्षीय संबंधों को धीरे-धीरे सामान्य और स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत लगातार यह स्पष्ट करता रहा है कि दोनों देशों के रिश्तों में निरंतर प्रगति के लिए सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना जरूरी है। शाम 5:45 बजे पीएम मोदी से मुलाकात शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शनिवार शाम करीब 5:45 बजे द्विपक्षीय बैठक होने की उम्मीद है। हाल ही में बिश्केक में हुए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच संक्षिप्त बातचीत हुई थी। अब नई दिल्ली में होने वाली बैठक में दोनों देशों के बीच संबंधों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की संभावना है। भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने भी पहले संकेत दिया था कि बीजिंग और नई दिल्ली, शी

जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक की तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि चीन दोनों नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन को लागू करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है।

पीएम मोदी संग ईरानी राष्ट्रपति मुश्किल दौर में मजबूत होते रिश्ते

नई दिल्ली।

हाल ही में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एक तस्वीर ने वैश्विक भू-राजनीतिक गलियारों में खूब सुर्खियां बटोरी। यह तस्वीर थी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की, जिसमें वे भारत मंडपम में एक-दूसरे का हाथ पकड़े चल रहे थे। इस दौरान एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत और पीएम मोदी के साथ अपने संबंधों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने कमान संभाली है, दोनों देशों के रिश्ते तेजी से ठीक हो रहे हैं।

राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारे संबंध, जब से मैंने कार्यभार संभाला है, तेजी से बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने बिना नाम लिए अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। ईरानी राष्ट्रपति ने भारत और ईरान के बीच गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को भी रेखांकित किया, जिसे उन्होंने समय के साथ न बदलने वाली एक मजबूत कड़ी बताया।यह भारत दौरा उस महत्वपूर्ण समय पर हो रहा है, जब ईरान अमेरिका और इजरायल के साथ 28 फरवरी से चल रहे युद्ध के खतरनाक मोड़ पर है। पश्चिम एशिया में संकट गहरा रहा है, होर्मुज और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य में जहाजों की सामान्य आवाजाही बाधित है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम फिर आसमान छू रहे हैं।

अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों के साथ ईरान के रिश्ते अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, और हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब पर हमलों ने स्थिति को और जटिल कर दिया है।

वैश्विक चुनौतियों के बीच महाशक्तियों का मिलन, भारत देगा नए मंत्र

दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आगाज

नई दिल्ली।

आज 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का औपचारिक आगाज हो गया है। भारत मंडपम में 12 और 13 सितंबर को होने वाली इस बैठक में ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन दिल्ली पहुंच चुके हैं, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज भारत पहुंचेंगे। इस समिट पर दुनिया भर की नजरें इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, वैश्विक व्यापार तनाव और बदलती विश्व व्यवस्था के बीच ब्रिक्स की भूमिका पर अहम चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शी जिनपिंग के साथ प्रस्तावित मुलाकात भी इस सम्मेलन के सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रमों में से एक होगी। शिखर सम्मेलन से पहले भारत मंडपम में सुरक्षा जांच चल रही है, जहां ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों के नेताओं के साथ-साथ आमंत्रित प्रतिनिधि भी एक साथ आ रहे हैं। इस साल का विषय है- लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य भारत ने इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में इसकी अध्यक्षता की है। ब्रिक्स देशों और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका पर चीन के वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि उन्होंने लगभग 20 साल पहले भारत में काम किया था और अब

जब वह दोबारा यहां आए हैं, तो उन्होंने पाया कि भारत ने बहुत तेजी से विकास किया है, जिसमें गगनचुंबी इमारतें, मॉल और औद्योगिक पार्क शामिल हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने साथ लगभग 400 लोगों का प्रतिनिधिमंडल लेकर भारत पहुंच रहे हैं, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य और अन्य उच्चाधिकारी शामिल हैं, जो इस सम्मेलन के महत्व को दर्शाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं।

ब्रिक्स समिट के मुख्य मुद्दों में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देना शामिल है, ताकि आपसी व्यापार के लिए डॉलर के विकल्प के रूप में राष्ट्रीय मुद्राओं (जैसे रुपया, युआन, रूबल) का इस्तेमाल किया जा सके।

सर्पदंश के इलाज में भारतीय वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता

बेंगलुरु ।

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने सर्पदंश के इलाज की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों ने ऐसा रीकॉम्बिनेंट एंटीवेनम विकसित किया है. जो भारत में पाये जाने वाले कई जहरीली कोबरा प्रजातियों के घातक विष को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह शोध ढ्ढढ्ढस्ष्ठ के वैज्ञानिकों ने टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क के सहयोग से किया है। इस नई तकनीक में पारंपरिक तरीके से घोड़ों जैसे जानवरों से एंटीबॉडी हासिल करने के बजाय प्रयोगशाला में इंजीनियर्ड नैनोबॉडी और एंटीबॉडी तैयार की है। चूहों पर किए गए परीक्षणों में इस एंटीवेनम ने स्पेक्टेकल्ड कोबरा,

मोनोकल्ड कोबरा और किंग कोबरा के विष से मृत्यु रोकने में प्रभावी परिणाम दिए हैं । यह उपचार अभी मानवों में क्लीनिकल ट्रायल के चरण से गुजरना बाकी है। चूहों पर सफल ट्रायल कर ली गई है. वैज्ञानिकों का मानना है, सफलता मिलने पर भारत में सर्पदंश से होने वाली मौतों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी. भारत में हर साल 50000 से ज्यादा लोगों की सर्प दंस से मौत होती है.

भारत-चीन के बीच 6 साल बाद सीधी उड़ानें शुरू

- संबंधों में आ रहे सुधारों के संकेत

नई दिल्ली।

भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान सेवा लगभग छह साल के बाद फिर से शुरू हो गई है। चाइना सदर्न एयरलाइंस ने दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवाएं बहाल की हैं। यह खबर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आगमन से ठीक पहले सामने आई है, जहां वे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आ रहे हैं। इस कदम को भारत और चीन के बीच सुधरते रिश्तों के एक महत्वपूर्ण संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-2026 में शामिल होने के लिए भारत आ रहे शी जिनपिंग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है, जिसमें कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की संभावना है। चाइना सदर्न एयरलाइंस ने 12 सितंबर 2026 को घोषणा की कि वह 21 सितंबर से ग्वांगझू-नई दिल्ली मार्ग पर नियमित यात्री उड़ानें फिर से शुरू करेगी। यह सेवा लगभग 6 साल के अंतराल के बाद दोबारा शुरू की जा रही है। एयरलाइन ने बताया कि सेवा बहाल होने के बाद वह दक्षिण एशिया में 8 राउंड-ट्रिप मार्गों पर हर सप्ताह 100 से अधिक उड़ानों का संचालन करेगी। चीन की विमानन कंपनियों की ओर से भारत के लिए सीधी उड़ानों की बहाली दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले अप्रैल में एयर चाइना ने बीजिंग-दिल्ली सीधी उड़ान सेवा फिर शुरू की थी और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने 18 अप्रैल से कुनमिंग-कोलकाता के बीच सीधी उड़ानें दोबारा शुरू की थीं। भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने भी 30 मार्च को कोलकाता और शंघाई के बीच रोजाना नॉन-स्टॉप उड़ान सेवा शुरू की थी, जिससे भारत-चीन हवाई संपर्क को और मजबूती मिली। इंडिगो इससे पहले कोलकाता-ग्वांगझू उड़ान सेवा बहाल कर चुकी है और बाद में दिल्ली से भी चीन के लिए परिचालन शुरू किया था। भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें कोविड-19 महामारी के दौरान निलंबित हुई थीं। इसके बाद डोकलाम और गलवान गतिरोध के चलते दोनों देशों के संबंधों में आए तनाव का भी हवाई संपर्क पर असर पड़ा था। अब दोनों देशों के बीच संबंधों में कुछ

सुधार के बीच सीधी उड़ानों की बहाली को लोगों के बीच संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इस बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बीजिंग से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

धार्मिक अल्पसंख्यक एवं साम्प्रदायिक राष्ट्रवादः किस ओर जा रहा है भारत?

धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करने वालों ने भारत को 'विशेष चिंता वाले' राष्ट्रों की श्रेणी में रखा है। यूनाईटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (यूएससीआईआरएफ), जो एक स्वतंत्र संघीय संस्था है, ने भागवत के अमेरिका पहुंचने के कुछ ही दिन पहले एक वक्तव्य जारी कर कहा कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति में गिरावट जारी है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा एवं उनके विरूद्ध आम लोगों को उकसाने का काम नियमित तौर पर किया जा रहा है और आरएसएस से जुड़े समूहों की इस हिंसा में भागीदारी है।

(लेखक - राम पुनियानी)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का तीन देशों का दौरे के बाद विश्लेषक इस पर अपनी-अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। कुछ ने यह कहते हुए भागवत की सराहना की है कि उन्होंने विविधता को हिन्दुत्व से जोड़कर उसे अधिक उदार बनाया है। क्या हिन्दुत्व किसी भी तरह से इतना उदार हो सकता है कि उसमें हमारे देश की समृद्ध धार्मिक विविधता समाहित हो सके?

किसी भी देश में विविधता का कितना सम्मान है, इसका अंदाजा उस देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति से लगाया जा सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी देश में लोकतंत्र की सेहत कैसी है, यह इस आधार पर जाना जा सकता है कि वहां अल्पसंख्यक कितने सुरक्षित हैं। वर्तमान में लोकतंत्र संबंधी सूचकांकों पर भारत की स्थिति लगातार गिरती जा रही है। हमें इसे अल्पसंख्यकों के हालात और वे स्वयं अपनी स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं, से जोड़कर देखना चाहिए। हालांकि कुछ मुस्लिम नेता और अन्य मुसलमान, जो बेहतर स्थिति में हैं, यह दावा कर सकते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों की हालत बद से बदतर नहीं हो रही है।

इसका मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पिछले कुछ वर्षों या एक दशक के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का आकलन किया जाए। हाल में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) द्वारा इन्हीं मुद्दों पर केन्द्रित एक बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें दिए गए विवरण से हमारे समाज के हालात अच्छी तरह प्रतिबिंबित होते हैं। भाजपा के 240 लोकसभा सदस्य और 117 राज्यसभा सदस्य हैं। इसके अलावा उसके करीब 1,516 विधायक हैं यानि केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय विधायिकाओं में उसके कुल 1,873 जनप्रतिनिधि हैं। इनमें से केवल 2 मुसलमान हैं - एक त्रिपुरा में और एक मणिपुर में!

पीयूसीएल द्वारा आयोजित इस बैठक में विभिन्न मानवाधिकार संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। जहां तक मुसलमानों का सवाल है, सामाजिक विमर्श में उनका दानवीकरण अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच चुका है।

दिल्ली में पुलिस द्वारा 4पीएम की दो पत्रकारों (शाहीन और नफीसा) की पिटाई तब और तेज हो गई जब उनके साथ मारपीट कर रहे अधिकारी को यह पता लगा कि ये दोनों महिला पत्रकार मुसलमान हैं। शुरूआत में इस समुदाय को नफरत और हिंसा का निशाना बनाया जाता था। अब लक्ष्य है उन्हें मताधिकार से वंचित करना।

इसकी शुरूआत हुई कुख्यात एनआरसी और सीएए से। चूंकि इसके खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए मुस्लिम महिलाओं के प्रतिरोध के पूरे देश में फैल जाने का डर था इसलिए इस प्रक्रिया को रोक दिया गया। इस बीच विशेष सघन पुनःनिरीक्षण (एसआईआर) के माध्यम से मुसलमानों के नाम मतदाता सूचियों से हटाने का नया तरीका खोज निकाला गया और इसे देश पर लाद दिया गया।

एक के बाद एक कई राज्यों में लाखों मतदाताओं के नाम, जिनमें से अधिकतर मुस्लिम या दलित हैं, मतदाता सूचियों से हटाए जा रहे हैं। इसकी सबसे स्पष्ट पुष्टि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों से हुई, जहां चुनाव के ठीक पहले 27 लाख से अधिक मतदाताओं को एसआईआर के माध्यम से मताधिकार से वंचित कर दिया गया।

पराकला प्रभाकर, जो एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एवं राजनैतिक टिप्पणीकार हैं, ने कहा है कि एसआईआर का उद्देश्य सिर्फ मतदाता सूचियों का पुनःनिरीक्षण करना नहीं है बल्कि इससे ''नागरिकों के दो वर्ग बन जाएंगे - पहला वह जो मतदान कर सकेगा, और दूसरा वह जो नहीं कर सकेगा''। जिस दर से मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से हटाए जा रहे हैं, उससे यह अनुमान है कि प्रक्रिया पूर्ण होने तक लगभग 16 करोड़ लोग अपना मताधिकार खो चुके होंगे। इस तरह एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज के कुछ वर्गों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी से वंचित कर दिया जाएगा।

जहां सर्वोच्च न्यायालय तक ने मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजरों के इस्तेमाल पर पाबंदियां लगाईं हैं लेकिन उत्तरप्रदेश सहित कई भाजपा-शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसे एक तमगे की तरह इस्तेमाल किया। इसके साथ ही परिसीमन का खतरा भी मंडरा रहा है जिससे भाजपा के बोलबाले वाले राज्यों के जनप्रतिनिधियों की संख्या में अधिक बढ़ोत्तरी होगी। ऐसी बड़ी-बड़ी चालें आरएसएस की कोख से निकली इस पार्टी द्वारा चली जा रही हैं। एक अन्य मोर्चे पर भाजपा सरकार ने पूरे वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया है जो संविधान सभा की गीत समिति के फैसले के विपरीत है। यह ऐसी स्थिति पैदा करने का प्रयास है जिसमें हिंदू देवियों की पूजा गैर-हिन्दुओं को भी करनी होगी।

भारत में धार्मिक स्वतंत्रता बहुत हद तक केवल एक खोखला शब्दभर रह गया है। एक के बाद एक कई राज्यों ने 'धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम' लागू किए हैं जिनका मुख्य प्रावधान यह है कि हिन्दुओं को धर्म परिवर्तन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और इसके बहाने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा सकते हैं। संघ परिवार का एक अन्य कार्यक्रम है 'घर वापसी' जिसके अंतर्गत आदिवासियों, दलितों और मुसलमानों को धर्मपरिवर्तित कर हिन्दू बनाया जाता है। यह कार्य देश के दूरदराज के इलाकों में जोरशोर से जारी है।

धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करने वालों ने भारत को 'विशेष चिंता वाले' राष्ट्रों की श्रेणी में रखा है। यूनाईटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (यूएससीआईआरएफ), जो एक स्वतंत्र संघीय संस्था है, ने भागवत के अमेरिका पहुंचने के कुछ ही दिन पहले एक वक्तव्य जारी कर कहा कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति में गिरावट जारी है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा एवं उनके विरूद्ध आम लोगों को उकसाने का काम नियमित तौर पर किया जा रहा है और आरएसएस से जुड़े समूहों की इस हिंसा में भागीदारी है।

स्तंभ लेखिका तवलीन सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा, ''हिन्दुत्व के अधिक साहसी योद्धा चर्चों में बलपूर्वक घुस जाते हैं और वहां हिंसा एवं तोड़फोड़ करके प्रार्थनासभाओं में बाधा डालते हैं। इन 'कौशलों' के वीडियो सोशल मीडिया पर डाले जाते हैं। इनमें से एक में मैंने देखा कि एक भाजपा नेत्री जबलपुर के एक चर्च में घुसकर आक्रामक लहजे में एक नेत्रहीन से बात कर रही है, और उसे धमकाते हुए उस पर हिन्दुओं का धर्मपरिवर्तन कर उन्हें ईसाई बनाने का प्रयास करने का आरोप लगा रही है...ईसाईयों के धार्मिक उत्सवों में खलल डालने के लगभग 100 प्रयास किए गए हैं और ऐसी लगभग सभी घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में हुई हैं। लेकिन ऐसा करने वाले एक भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया गया और एक भी मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर हिंसा की इन घटनाओं की निंदा नहीं की।''

कई अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी धर्मपरिवर्तन निरोधक कानून लागू किया गया है। यह कानून बलपूर्वक, धोखाधड़ी या लालच देकर धर्मपरिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही का रास्ता साफ करता है। जो भी व्यक्ति धर्मपरिवर्तन करने का इच्छुक है उसे 60 दिन पहले संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी। यदि इन नियमों का उल्लंघन होता है, तो चर्च के पदाधिकारियों या अन्य दोषी व्यक्तियों को सात साल की सजा दी जा सकती है। बीस नागरिक समाज संगठनों, जिनमें ईसाईयों के संगठन भी शामिल थे, ने 24 अगस्त 2026 को मुंबई में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की और यह कानून वापिस लिए जाने की मांग की। उन्होंने इसे 'निजी पसंद में दखलअंदाजी'' और भारतीय नागरिकों को संविधान में दी गई धर्म का पालन करने एवं प्रचार करने की गारंटी पर हमला बताया। इस पृष्ठभूमि में मुंबई क्षेत्र के चर्चों ने फैसला किया है कि वे चर्चों में प्रार्थना सभाओं में भाग लेने के लिए आने वालों से सहमतिपत्र पर हस्ताक्षर करवाना शुरू करेंगे।

प्रार्थना सभाओं पर हमलों के अलावा मानवीय कार्य करने वाले ईसाई स्वयंसेवी संगठनों को एक अन्य समस्या का सामना करना पड़ है- पैसे की किल्लत। नए एफसीआरए नियमों में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनसे मिशनरियों की परोपकारी गतिविधियां रूक जाएंगीं और उनके द्वारा दी जा रही मानवीय सहायता पर निर्भर गरीब लोग उससे वंचित हो जाएंगे।

यह है 'विविधता' को एक आलंरिक वाक्यांश की तरह इस्तेमाल करने वाले हिन्दुत्व राजनीति के वयोवृद्ध नेता मोहन भागवत के दावों की हकीकत।

(अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया। लेखक आईआईटी मुंबई में पढ़ाते थे और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म के अध्यक्ष हैं)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

संपादकीय

नस्लभेदी अमेरिका

यूं तो ट्रंप प्रशासन भारतीयों को नस्लीय आधार पर निशाना बनाने का मौका कभी नहीं छोड़ता, लेकिन हाल ही में अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी डीएचएस द्वारा जारी एक विवादित विज्ञापन ने उसकी संकीर्ण सोच को ही उजागर किया है। हालांकि, अमेरिका के हिंदू,सिख संगठनों और डेमोक्रेट नेताओं द्वारा पुरजोर विरोध करने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया वह विज्ञापन हटा लिया गया, जिसमें 'मिस्टर सिंह' को निशाना बनाया गया था। निश्चित रूप से इस अप्रिय घटना को सिर्फ एक पोस्ट हटाने के बावजूद नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरे अर्थों में यह अमेरिका में भारतीयों को लगातार निशाना बनाने की लगातार की जा रही कोशिशों का ही हिस्सा भर है। दरअसल, अमेरिका में बिना लाइसेंस वाले कमर्शियल ड्राइवरों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत जारी इस विज्ञापन में एआई के जरिये बनाई गई, एक दाढ़ी वाले गेहुंआ रंग के व्यक्ति की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ अभद्र भाषा के साथ चेतावनी वाला संदेश भी लिखा गया था- 'हमारी सड़कों से हट जाओ, तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता, मिस्टर सिंह।' उसके बाद धमकी दी गई थी, 'खुद देश छोड़कर चले जाओ या अंजाम भुगतो।' दशकों से पूरी दुनिया की सरकारों को मानवता, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, समरसता जैसे भारी-भरकम शब्दों के जरिये अस्थिर करने के प्रयासों में लगा अमेरिका अपनी इस कवायद से बेनकाब होता नजर आया है। स्वाभाविक रूप से इस विज्ञापन के सामने आने के बाद भारतीय-अमेरिकियों और सिख संगठनों के साथ-साथ डेमोक्रेट नेताओं ने भी इस पोस्ट को नस्लवादी और भेदभावपूर्ण बताकर घोर निंदा की है। इसमें दो राय नहीं कि आप्रवासन कानून को लागू करने या खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में कुछ भी गलत नहीं है। असल में, जब लापरवाही या आपराधिक व्यवहार के कारण मौतें होती हैं, तो सरकारों का यह भी कर्तव्य होता है कि वह कार्रवाई करें। लेकिन कानून का पालन व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर होना चाहिए न कि उसकी जाति, रूप-रंग, धर्म या उपनाम के आधार पर किया जाए। इसमें दो राय नहीं है कि भारतीय व अन्य प्रवासियों ने अपने खून-पसीने से अमेरिका की समृद्धि को सींचा है। उनकी समृद्धि अथक प्रयासों व कड़ी मेहनत का फल है जो आज गोरे अमेरिकनों को रास नहीं आता। अब तक भारतवंशियों का विरोध अमेरिका में गुपचुप ढंग से होता था, ट्रंप के शासनकाल में वह खुलकर सामने आने लगा है। अमेरिका की एक जिम्मेदार फेडरल एजेंसी डीएचएस जब इस तरह का कृत्य करती है तो यह शर्मनाक ही कहा जाएगा। उसके विज्ञापन में भारत में आदर से लिये जाने वाले 'सिंह' उपनाम का दुर्भावना से प्रयोग किया जाना विशेषकर चिंता की बात है। यह उपनाम सिखों में आम है और कुछ हिंदू भी इसका प्रयोग करते हैं। इस शब्द को गैर-कानूनी आप्रवासन या खतरनाक ड्राइविंग से जोड़ने से एक आम सांस्कृतिक पहचान को एक मजाक में बदले जाने का खतरा पैदा होता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि सिख समुदाय को 9/11 के हमलों के बाद लगातार नफरत प्रेरित अपराधों का सामना करना पड़ा था। उनकी पहचान को अज्ञानतावश हमलावरों से जोड़ कर देखा जा रहा था। इस समुदाय के लिये यह दंश झेलना बेहद कष्टकारी रहा है। डीएचएस यह दलील दे सकता है कि इस अभियान का मकसद गंभीर अपराधों के आरोपी विदेशी नागरिकों से जुड़े कुछ खास मामलों को उजागर करना था। यदि ऐसा है तो इन मामलों की जांच होनी चाहिए।

क्या ब्रिक्स बनेगा नई विश्व व्यवस्था का इंजन?

(लेखक- एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं)

-भारत के क्रिटिकल मिनरल्स दांव से हिल गए ट्रंप? -अमेरिका,चीन और पश्चिम की बढ़ी चिंता! -क्या क्रिटिकल मिनरल्स बदलेंगे दुनियाँ की चाल?

ब्रिक्स 2026 का मूल मंत्र बिल्डिंग फॉर रेसिलिन्स, इन्नोवेशन, कोआपरेशन एंड सस्टेंएंबिलिटी तथा ह्यूमनिटी फर्स्ट, भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर

ब्रिक्स 2026 क़ी अध्यक्षता भारत के लिए केवल एक कूटनीतिक उपलब्धि नहीं बल्कि 21वीं सदी की नई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत के बढ़ते कद की निर्णायक घोषणा बन सकती है

वैश्विक स्तरपर दुनियाँ इस समय जिस दौर से गुजर रही है,उसमें युद्ध, व्यापारिक टकराव,ऊर्जा संकट, आपूर्ति-श्रृंखला की अस्थिरता, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और महाशक्तियों के बीच बढ़ती भू-राजनीतिक खींचतान ने वैश्विक व्यवस्था को अभूतपूर्व अनिश्चितता के दौर में पहुंचा दिया है। ऐसे समय में 12-13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में हो रहे 18 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन केवल एक सामान्य कूटनीतिक बैठक नहीं है, बल्कि यह इस बात की परीक्षा भी है कि उभरती अर्थव्यवस्थाएं बदलती विश्व व्यवस्था में अपनी सामूहिक शक्ति को कितना प्रभावी बना सकती हैं। भारत 2026 में चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और उसकी अध्यक्षता का मूल मंत्र बिल्डिंग फॉर रेसिलिन्स, इन्नोवेशन, कोआपरेशन एंड सस्टेंएंबिलिटी तथा ह्यूमनिटी फर्स्ट है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र बताना चाहूंगा क़ि,सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिक्स अब केवल ब्राजील,रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का पुराना समूह नहीं रह गया है। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के पूर्ण सदस्य बनने के बाद यह 11 सदस्यीय समूह बन चुका है। ब्रिक्स देशों में दुनियाँ की करीब आधी आबादी रहती है और क्रय-शक्ति समानता के आधार पर वैश्विक जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत के आसपास है। यही वजह है कि नई दिल्ली में होने वाला सम्मेलन पश्चिमी देशों सहित पूरी दुनियाँ की निगाहों के केंद्र में है।

साथियों,भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का एजेंडा केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रखा गया है। व्यापार,निवेश,ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल तकनीक एमएसएमई स्टार्टअप,वैश्विक मूल्य- श्रृंखलाओं,पर्यावरण आपदा-रोधी क्षमता और भुगतान प्रणालियों जैसे व्यावहारिक मुद्दों पर पूरे वर्ष बैठकें हुई हैं। जयपुर में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2030 की दिशा में प्रगति,व्यापार वित्त की कमी दूर करने के लिए जयपुर सहमति और अधिक मजबूत तथा विविध वैश्विक मूल्य- श्रृंखलाओं पर जोर दिया गया। इसी तरह गुरुग्राम में ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्मार्ट ग्रिड तथा ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस की सटीकता से शुरुआत हुई।

साथियों,इसी व्यापक आर्थिक रणनीति के बीचक्रिटिकल मिनरल्स भारत की अध्यक्षता का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक पहलू बनकर उभर रहे हैं।लिथियम, निकेल कोबाल्ट ग्रेफाइट, कॉपर, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और प्लेटिनम ग्रुप की धातुएं आज केवल खनिज नहीं रह गई हैं; ये इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, सेमीकंडक्टर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, रक्षा प्रणालियों एयरोस्पेस, दूरसंचार और आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था की बुनियादी ताकत बन चुकी हैं। इसलिए जिस देश या समूह के पास इन खनिजों के भंडार, खनन, प्रोसेसिंग और तकनीक पर नियंत्रण होगा, उसके पास भविष्य की औद्योगिक शक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।यही कारण है कि ब्रिक्स में क्रिटिकल मिनरल्स का महत्व तेजी से बढ़ा है। 2024 के कज़ान शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के विशाल खनिज भंडार को देखते हुए भूवैज्ञानिक सहयोग और ब्रिक्स जियोलॉजिकल प्लेटफार्म को व्यावहारिक सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया था।इसका उद्देश्य भूवैज्ञानिक जानकारी,संसाधन आकलन, खनन तकनीक और खनिज संसाधनों के तर्कसंगत विकास में सहयोग बढ़ाना है।ब्रिक्स के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार समूह के पास दुनिया के रेयर-अर्थ मिनरल रिजर्व का लगभग 72 प्रतिशत हिस्सा है।

साथियों,यहां भारत की रणनीति बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत के पास रेयर अर्थ और ग्रेफाइट जैसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं, ब्राजील के पास रेयर अर्थ के साथ लिथियम और कॉपर की क्षमता है, रूस के पास निकेल, कॉपर और अन्य रणनीतिक खनिज हैं, दक्षिण अफ्रीका और रूस प्लेटिनम ग्रुप मेटल्स में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, जबकि इंडोनेशिया निकेल की वैश्विक आपूर्ति में बेहद बड़ा खिलाड़ी है।यानी ब्रिक्स देशों की ताकतें एक-दूसरे की कमियों को पूरा कर सकती हैं।समस्या यह है कि जिन देशों के पास संसाधन हैं,उनके पास हमेशा प्रोसेसिंग और डाउनस्ट्रीम तकनीक नहीं है; वहीं जिन देशों के पास बड़ा बाजार, पूंजी और औद्योगिक क्षमता है, उनके पास पर्याप्त घरेलू भंडार नहीं हैं।यदि यह बिखरी हुई क्षमता एक साझा मूल्य- श्रृंखला में बदलती है, तो ब्रिक्स क्रिटिकल मिनरल्स में एक अत्यंत प्रभावशाली शक्ति बन सकता है।यहीं से उस सवाल का जवाब भी मिलता है कि भारत क्यों इस मुद्दे को इतना महत्व दे रहा है। भारत का उद्देश्य केवल खनिज खरीदना नहीं, बल्कि खनन से लेकर प्रोसेसिंग,रिफाइनिंग, तकनीक और अंतिम उत्पाद तक पूरी वैल्यू चेन में अपनी स्थिति मजबूत करना है। यह रणनीति चीन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने और भविष्य की तकनीकी तथा ऊर्जा अर्थव्यवस्था के लिए वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत बनाने से जुड़ी है। भारत पहले ही ब्रिक्स के भीतर अधिक लचीली और विविध वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखलाओं की सटीकता से वकालत कर चुका है।

साथियों इसका असर वैश्विक राजनीति पर भी पड़ सकता है। यदि किसी एक देश के पास किसी महत्वपूर्ण खनिज की खनन और प्रोसेसिंग क्षमता अत्यधिक केंद्रित हो और वह आपूर्ति को राजनीतिक दबाव के लिए इस्तेमाल करे, तो पूरी दुनिया की औद्योगिक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। भारत इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण खनिजों को राजनीतिक हथियार बनाए जाने के खिलाफ आपूर्ति-श्रृंखलाओं को सुरक्षित, विविध और विश्वसनीय बनाने की दिशा में सहयोग की वकालत कर रहा है।इसलिए क्रिटिकलमिनरल्स का मुद्दा अब केवल आर्थिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता का प्रश्न बन चुका है।

साथियों, इस पूरी कहानी में चीन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। चीन ब्रिक्स का सबसे बड़ा आर्थिक और औद्योगिक खिलाड़ी है और रेयर अर्थ की वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखला में उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच सीमा विवाद तथा 2020 के गलवान संघर्ष के बाद पैदा हुआ विश्वास का संकट अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।

क्या हैं आध्यात्मिक होने का अर्थ

यह प्रश्न किसी भी जिज्ञासु के मन में उठ सकता है कि हमें ठीक-ठीक ऐसा क्या करना चाहिए ताकि वह जो परम है, जो परमेश्वर है, वह मेरे जीवन में घटित हो सके? सदगुरु इसका उत्तर देते हैं कि अध्यात्म भीगी बिल्लियों के लिए नहीं है, क्या तुम समझ रहे हो? तुम अपने जीवन में और कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन सोचते हो कि मैं आध्यात्मिक हो सकता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर तुम इस संसार के किसी भी काम को अपने हाथ में लेकर कर सकते हो, फिर तुम्हारे आध्यात्मिक होने की एक संभावना पैदा हो सकती है, अन्यथा नहीं। अगर तुम्हारे पास इस संसार के किसी भी काम को लेकर और अच्छी तरह से करने की शक्ति और साहस है, तब तुम संभवतः आध्यात्मिक हो सकते हो।

यह उन लोगों के लिए नहीं है, जो कुछ भी नहीं कर सकते। अभी, पूरे देश के मन में यही बैठा हुआ है, संभवतः पूरे संसार के मन में, कि वे निकम्मे और नालायक लोग, आध्यात्मिक लोग होते हैं, क्योंकि वे तथाकथित आध्यात्मिक लोग वैसे ही हो गए हैं। वे लोग जो किसी भी चीज को करने के लायक नहीं हैं, वे बस यही करते हैं कि एक गेरुआ वस्त्र पहन कर और किसी मंदिर के सामने बैठ जाते हैं; उनका जीवन सँवर जाता है। यह अध्यात्म नहीं है, यह वर्दी पहनकर बस भीख माँगना है। अगर तुम्हें अपनी चेतना पर विजय प्राप्त करनी है, अगर तुम्हें अपनी चेतना के शिखर पर पहुँचना है, वहाँ एक भिखारी कभी नहीं पहुँच सकता। दो तरह के भिखारी होते हैं। गौतम बुद्ध तथा उस स्तर के लोग उच्चतम श्रेणी के भिखारी हैं। दूसरे सभी निपट भिखारी हैं। मैं तो कहूँगा कि एक सड़क का भिखारी तथा राजगद्दी पर बैठा हुआ एक राजा, दोनों ही भिखारी हैं। वे निरन्तर बाहर से कुछ माँग रहे होते हैं। सड़क का भिखारी हो सकता है कि पैसा, भोजन या आय माँग रहा हो। राजा हो सकता है कि किसी दूसरे राज्य पर विजय, खुशी या कुछ इस तरह की अनर्गल चीजें माँग रहा हो। क्या तुम देखते हो, हर व्यक्ति किसी न किसी चीज की भीख माँग रहा हैः गौतम बुद्ध ने केवल अपने भोजन के लिए भिक्षा माँगी, शेष चीजों के लिए वे आत्मनिर्भर थे। दूसरे सभी लोग, बस एक ही चीज के लिए भीख नहीं माँगते, अपना भोजन भीख में नहीं माँगते, बाकी सभी चीजों के लिए भीख माँगते हैं। उनका पूरा जीवन ही भीख माँगना है। केवल भोजन अर्जित करते हैं। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति, केवल भोजन के लिए भिक्षा माँगता है, अन्य सभी चीजें अपने भीतर से अर्जित करता है। जिस भी तरह से रहना तुम बेहतर मानते हो, उसी तरह से रहो। जिस भी तरह से रहने को तुम जीने का एक सशक्त ढंग मानते हो, उसी तरह से जिओ।

पर्युषण महापर्व : आत्मशुद्धि से आत्मजागरण की ओर

(लेखक - ललित गर्ग)

जैन धर्म का प्रमुख आध्यात्मिक महाकुंभ पर्युषण महापर्व इन दिनों देशभर में त्याग, तपस्या, संयम, साधना और आत्मचिंतन के साथ मनाया जा रहा है। यह केवल आठ दिनों तक चलने वाला धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने, जीवन को परिष्कृत करने और संबंधों को मधुर बनाने का अनुपम अवसर है। इस महापर्व का शीर्ष दिवस संवत्सरी 14 सितंबर को मनाया जाएगा और इसके पश्चात 15 सितंबर को क्षमापना एवं विश्व मैत्री दिवस के रूप में एक-दूसरे से क्षमा मांगने और क्षमा करने की भावना को अभिव्यक्त किया जाएगा। वास्तव में पर्युषण का यह क्रम व्यक्ति को आत्मशुद्धि से विश्वमैत्री तक ले जाने वाली एक सुंदर आध्यात्मिक यात्रा है। पर्युषण का वास्तविक अर्थ है-बाहर से भीतर की ओर लौटना, आत्मा में अवस्थित होना और अपने जीवन में जमी हुई कषायों, विकारों एवं प्रमाद की परतों को हटाना। मनुष्य का अधिकांश जीवन बाहरी उपलब्धियों, प्रतिस्पर्धाओं, इच्छाओं और दूसरों को देखने-परखने में बीत जाता है। वह संसार को बदलने की चिंता करता है, लेकिन स्वयं के भीतर झांकने का अवसर बहुत कम निकालता है। पर्युषण उसे ठहरने, अपने भीतर उतरने और स्वयं से साक्षात्कार करने का संदेश देता है। यही कारण है कि यह पर्व जप, तप, स्वाध्याय, ध्यान, सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आत्मावलोकन के माध्यम से जीवन को भीतर से निर्मल बनाने का अवसर बनता है।

आज दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, उसमें पर्युषण की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। परिवारों में संबंधों की गर्माहट कम हो रही है, समाज में वैचारिक दूरियां बढ़ रही हैं, आर्थिक प्रतिस्पर्धा ने मनुष्य को अधिकाधिक पाने की दौड़ में लगा दिया है और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अनेक बार संवाद की जगह टकराव को जन्म देती है। राष्ट्रों के बीच अविश्वास, संघर्ष, हिंसा और आतंक की घटनाएं मानवता को चुनौती दे रही हैं। ऐसी स्थिति में जैन धर्म का पर्युषण महापर्व यह संदेश देता है कि बाहरी शांति का मार्ग भीतर की शांति से होकर जाता है। जब तक मनुष्य अपने भीतर के क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, आग्रह और द्वेष को कम नहीं करेगा, तब तक परिवार, समाज और विश्व में स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकती। पर्युषण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश आत्मावलोकन है। प्रतिक्रमण इसी आत्मावलोकन की वैज्ञानिक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। 'प्रति' अर्थात वापस और 'क्रमण' अर्थात लौटना-अर्थात् अपनी भूलों से वापस लौटकर अपने वास्तविक स्वरूप की ओर आना। असत्य से सत्य की ओर, अशुभ से शुभ की ओर, प्रमाद से अप्रमाद की ओर और वैर से मैत्री की ओर लौटना ही प्रतिक्रमण की सार्थकता है। मनुष्य से जाने-अनजाने में भूलें होती हैं। समस्या भूल होने में उतनी नहीं है, जितनी उसे स्वीकार न करने में है। जो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर सुधार की संभावना पैदा होती है, जो अपनी भूल को सही साबित करने में लगा रहता है, वह अपने विकास का मार्ग स्वयं बंद कर देता है। संवत्सरी इसी आत्मशोधन की चरम अभिव्यक्ति है। वर्षभर के व्यवहार, विचार और कर्मों की समीक्षा करते हुए व्यक्ति स्वयं से प्रश्न करता है-मैंने किसे दुख पहुंचाया? किसके प्रति मेरे मन में द्वेष पैदा हुआ? मेरे शब्दों से किसका मन आहत हुआ? मेरे व्यवहार में कहां अहंकार आया? कहां लोभ, क्रोध या आग्रह ने मुझे संचालित किया? इस आत्ममंथन से भीतर का बोझ हल्का होता है। क्षमा मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल का परिचायक है। अपनी गलती स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए और दूसरे की गलती को क्षमा करने के लिए उससे भी बड़ा हृदय चाहिए। पर्युषण का अंतिम संदेश क्षमापना और विश्व मैत्री है। यह केवल औपचारिक रूप से 'मिच्छामि दुक्कडम्' कह देने का अवसर नहीं है, बल्कि अपने भीतर से वैर और कटुता को विसर्जित करने का संकल्प है। क्षमा तभी सार्थक है जब वह मन से हो। यदि शब्दों से क्षमा मांग ली जाए और हृदय में शिकायत बनी रहे, तो क्षमापना अधूरी रह जाती है। इसी तरह किसी से क्षमा मांगने का अर्थ स्वयं को छोटा करना नहीं, बल्कि संबंधों को बड़ा बनाना है। भगवान महावीर का संदेश-'मित्ती मे सव्व भूएसु, वेरं मज्झं न केणइ'-अर्थात् सभी प्राणियों के साथ मेरी मैत्री है, किसी के साथ मेरा वैर नहीं है-आज की दुनिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीमद्भगवद्गीता में भी श्रीकृष्ण अर्जुन को आत्मौपम्य की दृष्टि देते हुए कहते हैं कि जो सभी प्राणियों को अपने समान देखता है, वही श्रेष्ठ दृष्टि वाला है। दोनों परंपराओं का मूल संदेश एक ही है-दूसरे के सुख-दुःख को अपने सुख-दुःख की तरह अनुभव करना। आज जब व्यक्तिगत संबंधों में कड़वाहट और दूरियां बढ़ रही हैं, तब पर्युषण परिवारों को भी नई दृष्टि दे सकता है। पति-पत्नी, माता-पिता और संतान, भाई-बहन, मित्र और सहकर्मी-यदि एक-दूसरे की अपेक्षाओं के बजाय एक-दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, तो अनेक विवाद अपने आप समाप्त हो सकते हैं। हर व्यक्ति अपने अधिकार की बात करता है, लेकिन यदि कर्तव्य और संवेदना को भी उतना ही महत्व मिले, तो संबंधों में मधुरता लौट सकती है। क्षमा संबंधों की मरम्मत करने वाली ऐसी शक्ति है, जो टूटे हुए विश्वास को भी धीरे-धीरे जोड़ सकती है। पर्युषण का संदेश केवल जैन समाज तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अहिंसा, संयम, क्षमा, मैत्री और सह-अस्तित्व सार्वभौमिक जीवन-मूल्य हैं। धार्मिक आस्था अलग हो सकती है, पूजा-पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन मनुष्य को मनुष्य के रूप में सम्मान देना किसी एक धर्म की सीमा नहीं है। हिंसा किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकती। हिंसा प्रतिशोध को जन्म देती है और प्रतिशोध नई हिंसा को। इसके विपरीत संवाद, सहिष्णुता, क्षमा और मैत्री समाधान की संभावनाओं को जन्म देते हैं। आज विश्व आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक प्रतिस्पर्धा के चरम दौर में है। राष्ट्र अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हैं, बाजार अधिकाधिक विस्तार चाहता है और तकनीक ने मनुष्य की क्षमताओं को अभूतपूर्व बनाया है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

ड्राईडॉक्स वर्ल्ड, कोचीन शिपयार्ड ने संयुक्त उद्यम का किया गठन

नई दिल्ली।

डीपी वर्ल्ड समूह की कंपनी ड्राईडॉक्स वर्ल्ड और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने कोचीन जहाज मरम्मत सुविधा के संचालन और विस्तार के लिए एक संयुक्त उद्यम (जेवी) समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। डीपी वर्ल्ड ने एक बयान में कहा कि यह 50-50 की साझेदारी वाला संयुक्त उद्यम कोचीन स्थित इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी (आईएसआरएफ) का संचालन और विस्तार करेगा, जिससे भारत का जहाज मरम्मत परिवेश मजबूत होगा तथा बढ़ती क्षेत्रीय और वैश्विक मांग पूरी होगी। पोत परिवहन मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि ड्राईडॉक्स वर्ल्ड और सीएसएल दोनों इस परियोजना में 900-900 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। इस समझौते पर ड्राईडॉक्स वर्ल्ड के सीईओ कैप्टन राडो एंटोलोविक (पीएचडी) और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक जोस वीजे ने नयी दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के मौके पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा यूएई के उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मामलों के सहायक विदेश मंत्री इमरान शराफ अलहाशिमी उपस्थित थे।

तेलंगाना में एनालॉग पनीर के उत्पादन, बिक्री पर रोक

हैदराबाद ।

तेलंगाना सरकार ने जनस्वास्थ्य के हित में राज्य में गैर-डेयरी, कृत्रिम पनीर या एनालॉग पनीर के विनिर्माण, प्रसंस्करण, पैकिंग, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए रोक लगा दी है। तत्काल प्रभाव से लागू होने वाला यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। तेलंगाना खाद्य एवं आवश्यक औषधि मानक प्राधिकरण ने कहा कि तेलंगाना के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने जनस्वास्थ्य के हित में पूरे राज्य में किसी भी रूप में गैर-डेयरी, कृत्रिम पनीर या एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। विज्ञप्ति के अनुसार यह प्रतिबंध 10 सितंबर से तत्काल प्रभाव से एक साल के लिए लागू होगा।

कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बावजूद देश में पेट्रोल-डीजल स्थिर

ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर, भविष्य में बढ़ने की आशंका बरकरार

नई दिल्ली ।

देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें शे निवार को भी स्थिर बनी हुई हैं, जिससे उपभोक्ताओं को एक बार फिर राहत मिली है। सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन के खुदरा दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। यह लगातार 25 मई से जारी स्थिरता है, बावजूद इसके कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं, जिससे भविष्य में दाम बढ़ने की चिंता बनी हुई है। करीब साढ़े तीन महीने से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम जस के तस बने हुए हैं। 12 सितंबर को भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें कल जितनी ही हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111.31 रुपये और डीजल 97.97 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 107.78 रुपये और डीजल 99.56 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपये और डीजल 99.82 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर हैं। गुरुग्राम, पटना, नागपुर, श्रीनगर और इंदौर जैसे अन्य शहरों में भी कीमतें पूर्ववत बनी हुई हैं। हालांकि, घरेलू बाजार में यह स्थिरता अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से बिल्कुल अलग है, जहां कच्चे तेल की कीमतें चिंता का विषय बनी हुई हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने कच्चे तेल की आपूर्ति और कीमतों को लेकर वैश्विक चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का महंगा होना देश के आयात बिल और समग्र अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, साथ ही लंबे समय तक ऊंचे दाम बने रहने से परिवहन लागत में वृद्धि हो सकती है। भारत में ईंधन की कीमतें डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग व्यवस्था के तहत हर दिन सुबह 6 बजे संशोधित की जाती हैं। तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक उच्च स्तर पर बनी रहती हैं, तो देश में पेट्रोल-डीजल के खुदरा दामों पर इसका असर दिखना तय है और यह वर्तमान स्थिरता समाप्त हो सकती है। फिलहाल उपभोक्ताओं को मिली यह राहत कितने समय तक बरकरार रहेगी, यह अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल पर निर्भर करेगा।

'ब्रिक्स बाजार' में जुटी दुनिया भर की हस्तकलाएं

18 देशों के 40 से अधिक कारीगर, डिजाइनर अपनी अनूठी कलाओं का कर रहे प्रदर्शन

नई दिल्ली।

दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की गहमागहमी के बीच, भारत मंडपम से कुछ ही दूरी पर स्थित राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में एक अनूठा सांस्कृतिक आयोजन ब्रिक्स बाजार शुरू हो गया है। यह प्रदर्शनी सदस्य और साझेदार देशों की समृद्ध कला और हस्तशिल्प को एक मंच पर ला रही है, जो वैश्विक सांस्कृतिक आदान-प्रदान का प्रतीक है। यह रचनात्मक प्रदर्शनी 15 सितंबर तक चलेगी, जिसमें 18 देशों के 40 से अधिक कारीगर, डिजाइनर और रचनात्मक कंपनियां अपने बेहतरीन उत्पाद और कलाकृतियां पेश कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों के अलावा सहयोगी देशों की चीन की सूझोउ कढ़ाई, इंडोनेशिया की पारंपरिक बुनाई, नाइजीरिया की लकड़ी की कला और दक्षिण अफ्रीका की जुलू चमड़ा कला जैसी प्रामाणिक हस्तकलाएं दर्शकों को लुभा रही हैं। भारत भी अपनी सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन कर रहा है, जहां रियाज अहमद की कश्मीरी पेपर मेश, मोहम्मद बिलाल खत्री की ब्लॉक प्रिंट, करण सिंह की टेराकोटा कला और शादाब अहमद की लाख की चूड़ियां विशेष आकर्षण हैं। मेजबान देश ने जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों की पारंपरिक जीवनशैली को दर्शाते विशेष

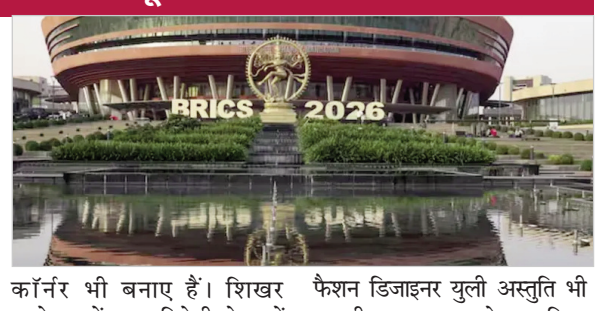

कॉर्नर भी बनाए हैं। शिखर सम्मेलन में आए विदेशी मेहमानों और उनके परिवारों के भी इस अनूठे शिल्प मेले का दौरा करने की उम्मीद है।

प्रदर्शनी में लुइस फारिनास लियोन (क्यूबा) जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित कलाकार शामिल हैं, जिन्हें 2023 में लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था। इंडोनेशिया की प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर युली अस्तुति भी अपनी लुप्तप्राय कुडोस बाटिक डिजाइनों को पुनर्जीवित करने के लिए जानी जाती हैं। यह बाजार सिर्फ उत्पादों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि दुनियाभर के कारीगरों को अपनी कला के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और वैश्विक पहचान बनाने का एक अनमोल अवसर भी प्रदान करता है।

आरबीआई एक लाख करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियां बेचेगी

मुंबई ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने तीन चरणों में खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) के तहत एक लाख करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियां बेचने की घोषणा की। पहला चरण 17 सितंबर को होगा। आरबीआई के अनुसार पहले चरण में 17 सितंबर को 50,000 करोड़ रुपए और उसके बाद 21 सितंबर तथा 28 सितंबर को 25,000-25,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियां बेची जाएंगी। आरबीआई ने बयान में कहा` कि बैंकिंग प्रणाली में उपलब्ध धन की मौजूदा स्थिति और उसमें हो रहे बदलाव की समीक्षा के बाद रिजर्व बैंक ने तीन चरणों में कुल एक लाख करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियां बेचने का फैसला किया है। पहली नीलामी में 2029, 2030, 2031 और 2032 में परिपक्व होने वाली सरकारी प्रतिभूतियां बेची जाएंगी। आरबीआई ने कहा कि नीलामी 17 सितंबर को सुबह साढ़े नौ बजे से साढ़े 10 बजे के बीच होगी। यह घोषणा ऐसे समय हुई है जब विदेशी मुद्रा प्रवासी (बैंक) (एफसीएनआर-बी) जमा के जरिये विदेशी मुद्रा आने से बैंकों में उपलब्ध धन काफी बढ़ गया है। अतिरिक्त धन को वापस लेने के लिए आरबीआई लगातार परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामी भी कर रहा है। बैंकों द्वारा एफसीएनआर (बी) जमा में बड़ी मात्रा में धन जुटाए जाने के बाद बैंकों में उपलब्ध नकदी में तेज वृद्धि हुई है।

'एआई दोधारी तलवार, सुरक्षा उपायों के बिना बेकाबू होने का खतरा'- निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली ।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को तेजी से अपनाने के साथ-साथ मजबूत सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि सुरक्षा मानकों के बिना एआई बेकाबू होकर समाज के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है, जिससे लंबे समय तक न टिकने वाले जोखिमों का वितरण होगा। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में बोलते हुए, सीतारमण ने वैश्विक एआई उद्योग में तेजी से विकसित हो रहे फ्रंटियर मॉडल और एक शोधकर्ता की स्वयं को बेहतर बनाने वाली सुपर-इंटेलिजेंस संबंधी सार्वजनिक चेतावनी का उल्लेख किया। उन्होंने इन जोखिमों की गंभीरता से जांच की मांग की और संस्थागत जवाबदेही पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने पूछा, जनता को कौन आश्वस्त करेगा कि सुरक्षा उपाय तकनीक की गति के साथ चल रहे हैं? भरोसेमंद व पारदर्शी जवाब देने के लिए सामूहिक प्रयास कहां है? सीतारमण ने एआई को दोहरी तलवार बताया, जो धोखाधड़ी का पता लगाने और बड़े साइबर हमलों को स्वचालित करने दोनों में सक्षम है। उन्होंने नियामकों और वरिष्ठ प्रबंधन को एआई गवर्नेंस को केवल तकनीकी टीमों पर न छोड़ने की सलाह दी, बल्कि इसके उपयोग, निर्णयों और डेटा को समझने पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने उच्च जोखिम वाले एप्लिकेशनों की गहन जांच की वकालत की। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि एआई को न अपनाने से भी संस्थान कमजोर पड़ सकते हैं और प्रतिस्पर्धात्मकता खो सकते हैं।

बीता सप्ताह भारतीय शेयर बाजार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा

बाजार में उथल-पुथल जारी रही, सेंसेक्स-निफ्टी लगातार दबाव में, निवेशकों को लगा बड़ा झटका

मुंबई ।

बीता सप्ताह भारतीय शेयर बाजार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा, जहां प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में भारी गिरावट दर्ज की गई। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक संघर्ष, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, और अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर चिंताओं ने निवेशकों की धारणा को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, जिससे बाजार में व्यापक बिकवाली का दबाव देखा गया। सप्ताह की शुरुआत से ही बाजार पर वैश्विक तनाव का साया मंडरा रहा था। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्षों के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल 100 डॉलर प्रति बैरल के निशान को पार करने की आशंका बढ़ गई, जिसने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा संभावित ब्याज दर वृद्धि की आशंका और विदेशी पूंजी की लगातार निकासी ने भी बाजार को कमजोर किया। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुझान का असर भारतीय सूचकांकों पर साफ दिखाई दिया। सप्ताह के शुरुआती तीन दिन (सोमवार, मंगलवार और बुधवार) बाजार के लिए बेहद खराब रहे। सोमवार को सेंसेक्स 382 अंक और निफ्टी 118 अंक गिरकर बंद हुए। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी रही, जहां सेंसेक्स 555 अंक लुढ़का और निफ्टी 23,700 के नीचे आ गया। बुधवार को बाजार में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई, जब सेंसेक्स 813 अंक टूटकर 74,764.23 पर और निफ्टी 203 अंक गिरकर 23,431.50 पर बंद हुआ। गुरुवार को बाजार में मामूली सुधार दिखा, सेंसेक्स 138 अंक और निफ्टी 46 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए, लेकिन यह राहत अल्पकालिक रही। शुक्रवार को एक बार फिर बाजार में गिरावट लौटी, हालांकि यह शुरुआती भारी

गिरावट से कुछ उबरकर बंद हुए, फिर भी सेंसेक्स 120 अंक और निफ्टी 79 अंक के नुकसान के साथ सप्ताह का अंत किया। सप्ताह के दौरान धातु, सूचना प्रौद्योगिकी, तेल-गैस, वित्तीय सेवाएँ और रियल्टी जैसे क्षेत्रों में भारी बिकवाली देखी गई। अधिकांश क्षेत्रीय सूचकांक लाल निशान में कारोबार कर रहे थे, जो बाजार में व्यापक कमजोरी को दर्शाता है। हालांकि, गुरुवार को पीएसयू बैंक और एनर्जी जैसे कुछ क्षेत्रों में चुनिंदा खरीदारी का रुझान देखा गया, लेकिन बाजार में अनिश्चितता और निवेशकों की सावधानी बनी रही। भारतीय रुपया भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर बंद हुआ, जो बाजार के नकारात्मक संकेतों को और पुष्ट करता है। कुल मिलाकर, यह सप्ताह निवेशकों के लिए उतार-चढ़ाव भरा और नुकसानदेह साबित हुआ।

गणेशोत्सव में सोने-चांदी की बंपर बिक्री, महंगाई भी बेअसर

4000 करोड़ के कारोबार का अनुमान, मुंबई में 200 टन सोना बिकने की उम्मीद

मुंबई ।

इस साल गणेशोत्सव ने देश के ज्वैलरी बाजार में एक अनोखी चमक बिखेर दी है। शादी-विवाह या अन्य पारंपरिक त्योहारों से हटकर, गणपति बप्पा के स्वागत और उनकी प्रतिमाओं को सजाने के लिए सोने-चांदी के आभूषणों की जोरदार मांग देखी जा रही है। उद्योग अनुमानों के मुताबिक, अकेले मुंबई में इस गणेशोत्सव के दौरान 200 टन से अधिक सोने की बिक्री हो सकती है, जबकि देशभर में यह आंकड़ा 4,000 करोड़ रुपए के कारोबार तक पहुंचने का अनुमान है। गणेशोत्सव शुरू होने से लगभग पांच दिन पहले ही ज्वैलरी बाजार में यह विशेष रौनक शुरू हो गई थी। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के अनुसार गणेश चतुर्थी तक करीब 4,000 करोड़ रुपये के कारोबार की उम्मीद है। घरों में स्थापित होने वाली गणेश प्रतिमाओं के लिए छोटे-बड़े आभूषणों की खरीदारी जोरों पर है। जावेरी बाजार के ज्वैलर्स गणपति बप्पा के लिए गणेश पादुका, नेकलेस, मोदक, चूहे, जासवंती के फूल, चेन, कान की बालियां और बाजूबंद जैसे खास गहने तैयार कर रहे हैं। इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए कारीगर दिन-रात काम कर रहे हैं, क्योंकि गणेश को मन्नतों का देवता माना जाता है और कई भक्त मन्नतें पूरी होने पर बड़े उत्साह से खरीदारी कर रहे हैं। मुंबई सर्राफा बाजार में हर दिन 200 से 225 करोड़ रुपये के गहने बिक रहे हैं। आभूषण कारोबारियों का कहना है कि सोने की बढ़ती कीमतों का खरीद पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार सोने के दाम लगभग 40 फीसदी ज्यादा होने के बावजूद, ज्वैलरी की मांग दोगुनी हो गई है। भक्ति और आस्था के आगे महंगाई फीकी पड़ गई है। ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, सिर्फ बप्पा की ज्वैलरी की मांग के चलते गणेशोत्सव के दौरान मुंबई सर्राफा बाजार में 200 टन से ज्यादा सोना बिकने की उम्मीद है। सोने के साथ-साथ चांदी के बाजार में भी जबरदस्त रौनक है। चांदी के मोदक और चूहे की सबसे ज्यादा मांग है, जिसमें 50 ग्राम से लेकर सवा किलो तक के चूहे शामिल हैं। इसके अलावा मुकुट, कंठहार, कड़े और पादुकाएं भी खूब खरीदी जा रही हैं। गणेश पंडालों के लिए जहां प्रतिमा के आकार के अनुसार कई गुना बड़े और आकर्षक आभूषण बनाए जा रहे हैं, वहीं घरों के लिए मौजूदा रुझानों के हिसाब से आभूषणों की बिक्री हो रही है।

एसबीआई ने आरबीआई से दरें बढ़ाने का आग्रह किया

- बैंक की शोध रिपोर्ट में अक्टूबर और दिसंबर में 0.25-0.25 प्रतिशत की वृद्धि का सुझाव

नई दिल्ली । भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक शोध रिपोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को अगले महीने नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत और फिर दिसंबर में इतनी ही वृद्धि करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम लगातार बाहरी झटकों, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और व्यापक मुद्रास्फीति दबाव से निपटने के लिए आवश्यक है। एसबीआई की इकोरैप रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल ही में कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गई हैं और इनके जल्द ही 123 डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इन भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच, रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यदि तेल की कीमतें उच्च स्तर पर बनी रहती हैं, तो अक्टूबर और नवंबर में मुद्रास्फीति 6.5 प्रतिशत या उससे अधिक हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक महीने पहले तक ब्याज दर में लंबे ठहराव की उम्मीद थी, लेकिन अब स्थिति में भारी बदलाव आया है। बैंक का यह सुझाव अमेरिकी फेडरल रिजर्व के संभावित कदमों से अप्रभावित है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 5-7 अक्टूबर को होनी है, जहाँ इन सिफारिशों पर विचार किया जा सकता है। केंद्रीय बैंक ने अगस्त में लगातार चौथी बार प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा था।

ब्रिक्स मंच पर भारत की डीप-टेक क्रांति, 37 स्टार्टअप वैश्विक निवेश की दौड़ में

शिक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में ब्रिक्स-भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी में प्रस्तुत किए स्वदेशी स्टार्टअप

नई दिल्ली । भारत अपने स्वदेशी प्रौद्योगिकी नवाचारों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित कर रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स-भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी में 37 भारतीय डीप-टेक स्टार्टअप पेश किए हैं। इन स्टार्टअप का लक्ष्य ब्रिक्स देशों के निवेशकों, कंपनियों और व्यापारिक दिग्गजों के साथ निवेश, प्रौद्योगिकी साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहुंच के अवसर तलाशना है। यह दो दिवसीय प्रदर्शनी 11-12 सितंबर को ब्रिक्स बिजनेस फोरम के साथ चल रही है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन 37 स्टार्टअप का चयन उन 120 नवाचारी कंपनियों में से किया गया है, जिन्होंने जून में फ्रांस के नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी में भाग लिया था। ये स्टार्टअप अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, बैटरी सामग्री, रोबोटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हैं। मंत्रालय का मानना है कि यह प्रदर्शनी बी2बी जुड़ाव, प्रौद्योगिकी साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहुंच को सुगम बनाएगी। साथ ही, यह भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत चिह्नित अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की ब्रिक्स शिक्षा पहल को भी बल देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी सहित ब्रिक्स नेताओं, सीईओ और वैश्विक निवेशकों के इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल होने की उम्मीद है। प्रदर्शनी में ध्रुव स्पेस, गैलेक्सी स्पेस सॉल्यूशंस और विसिग नेटवर्क्स जैसे अग्रणी स्टार्टअप शामिल हैं।

एसबीआई छोटे व्यवसायों की ऋण पात्रता आंकने यूपीआई आंकड़ों का करेगा इस्तेमाल

पिछले 18 महीनों में बैंक ने जीएसटी और पैन के आंकड़ों का इस्तेमाल कर एक लाख करोड़ के ऋण दिए

मुंबई ।

सार्वजनिक क्षेत्र का भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) जीएसटी पंजीकरण नहीं रखने वाले छोटी इकाइयों की ऋण पात्रता का आकलन करने के लिए यूपीआई लेनदेन के आंकड़ों का इस्तेमाल करने की व्यवस्था विकसित कर रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एसबीआई के एक अे धिकारी ने यहां आयोजित वैश्विक फिनटेक सम्मेलन में कहा कि यदि किसी कारोबार में नियमित बिक्री हो रही है तो यूपीआई लेनदेन को जीएसटी के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा` कि हम जीएसटी न रखने वाले कारोबारियों के लिए एक यूपीआई समाधान विकसित कर रहे हैं और यूपीआई लेनदेन को बिक्री के संकेतक के रूप में इस्तेमाल करेंगे।' तिवारी ने कहा कि जीएसटी के तहत पंजीकृत कारोबारियों को ऋण देने की चुनौती का बैंक समाधान कर चुका है और ऐसे मामलों में 10 मिनट के भीतर ऋण देने की स्थिति में है। पिछले 18 महीनों में बैंक ने जीएसटी और पैन के आंकड़ों का इस्तेमाल कर एक लाख करोड़ रुपये के ऋण दिए हैं। हालांकि, जीएसटी नंबर नहीं रखने वाले कारोबारियों के मामले में कठिनाइयां हैं और ऐसे में वैकल्पिक आंकड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यूपीआई भुगतान से जुड़े मुद्दे पर तिवारी ने कहा कि कर्ज देने वाले बैंक के पास हमेशा यह स्पष्ट जानकारी नहीं होती कि पैसा कहां जा रहा है। हालांकि, प्राप्तकर्ता बैंक और लेनदेन में मदद करने वाले तीसरे पक्ष के भुगतान ऐप के पास यह जानकारी होती है। उन्होंने कहा कि ग्राहक की सहमति से बैंक यूपीआई भुगतान और दूरसंचार कंपनियों से मिलने वाले आंकड़ों जैसे अन्य स्रोतों का इस्तेमाल करने वाले मॉडल के जरिये ऋण पात्रता का आकलन कर सकता है। एसबीआई को उम्मीद है कि नए आंकड़ों के आधार पर छोटे कारोबारियों को ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा। इससे छोटे कारोबारियों की ऋण संबंधी दिक्कतों को दूर करने में मदद मिलेगी।

इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल बाजार तेजी से हो रहा विस्तार

नई दिल्ली ।

देश में वर्ष 2026 के पहले आठ महीनों में जनवरी से अगस्त के बीच इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की खुदरा बिक्री 2,18,716 यूनिट तक पहुंच गई। बिक्री के यह आंकडे बना रहे हैं कि भारत में इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर यानी इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल बाजार तेजी से विस्तार कर रहा है। पिछले वर्ष इसी अवधि में 1,21,322 यूनिट की बिक्री हुई थी। इस तरह सालाना आधार पर बिक्री में करीब 80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। मौजूदा रफ्तार को देखते हुए कैलेंडर वर्ष 2026 में इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की कुल खुदरा बिक्री करीब 3.50 लाख यूनिट तक पहुंचने का अनुमान है।

इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग देश के अधिकांश हिस्सों में बढ़ी है। राज्य में जनवरी से अगस्त के दौरान 31,184 यूनिट बिकीं, जबकि 2025 की समान अवधि में यह आंकड़ा 20,564 यूनिट था।

इस तरह महाराष्ट्र में 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तेलंगाना 21,537 यूनिट की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर रहा और यहां 100 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कर्नाटक में 20,440 यूनिट बिकीं, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 56 प्रतिशत अधिक हैं। दिल्ली में 19,875 यूनिट की बिक्री के साथ 120 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। तमिलनाडु में 17,985 और केरल में 17,638 यूनिट बिकीं। गुजरात में 15,608 यूनिट के साथ बिक्री 139 प्रतिशत बढ़ी, जबकि राजस्थान में 15,423 यूनिट की बिक्री और 134 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई। उत्तर प्रदेश में 14,330 यूनिट बिकीं, जो 74 प्रतिशत अधिक हैं। आंध्र प्रदेश में 7,274 यूनिट की बिक्री के साथ 154 प्रतिशत, ओडिशा में 5,862 यूनिट के साथ 133 प्रतिशत और पंजाब में 4,812 यूनिट के साथ 103 प्रतिशत वृद्धि हुई।

हालांकि हरियाणा में बिक्री 49 प्रतिशत घटकर 1,929 यूनिट रह गई। छोटे बाजारों में भी तेजी रही। चंडीगढ़ में 177 प्रतिशत, उत्तराखंड में 142 प्रतिशत, बिहार में 120 प्रतिशत और जम्मू-कश्मीर में 128 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई। नगालैंड और लद्दाख में भी बिक्री वृद्धि क्रमश- 225 और 300 प्रतिशत रही। । भारत के 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों में इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की स्वीकार्यता में तेजी देखने को मिली है। हरियाणा को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिक्री में वृद्धि दर्ज की गई। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में देश में पहले स्थान पर रहा।

ओडिशा में लघु जलविद्युत परियोजनाओं के लिए 185 स्थल किए चिन्हित

उपमुख्यमंत्री बोले- पर्यावरण और विकास दोनों के लिए लाभकारी

भुवनेश्वर । ओडिशा सरकार ने राज्य में लघु जलविद्युत परियोजनाओं को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विशाल कुमार देव ने शुक्रवार को बताया कि राज्य में ऐसे 185 स्थलों की पहचान की गई है, जहां कुल 260 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता विकसित की जा सकती है। देव ने लघु जलविद्युत विकास पर आयोजित एक संवाद के दौरान कहा कि देश के कुल सतही जल संसाधनों का लगभग 11 प्रतिशत ओडिशा में होने के कारण लघु जलविद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने जोर दिया कि राज्य में बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं के साथ अब छोटे पैमाने की परियोजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। शुरुआत में चिन्हित किए गए 185 स्थलों पर 260 मेगावाट क्षमता विकसित की जा सकती है, और भविष्य में यह क्षमता बढ़ भी सकती है। उपमुख्यमंत्री के.वी. सिंह देव ने सत्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि लघु जलविद्युत परियोजनाएं पर्यावरण और विकास दोनों के लिए लाभकारी हैं। इन परियोजनाओं में मौजूदा सिंचाई नहरों और जल प्रवाह का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होती। इस संवाद में नीति-निर्माताओं और विशेषज्ञों ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की 2026-31 की लघु जलविद्युत विकास योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने पर चर्चा की। अधिकारियों के अनुसार, भारत ने अपनी अनुमानित 21,133 मेगावाट की लघु जलविद्युत क्षमता में से अब तक 5,171 मेगावाट का उपयोग किया है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

ओडिशा टी-20 लीग 2026

सीएम ट्रॉफी के ब्रांड एंबेसडर बने रैना और देबाशीष मोहंती

कटक। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और देबाशीष मोहंती को **'ओडिशा टी 20 लीग'** 2026 सीएम ट्रॉफी का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है। यह टूर्नामेंट 20 से 29 सितंबर तक कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। इन दो पूर्व भारतीय क्रिकेटरों की नियुक्ति से टूर्नामेंट की अहमियत और बढ़ जाएगी। इस टूर्नामेंट का मकसद ओडिशा के युवा और उभरते हुए क्रिकेटरों को अपना हुनर दिखाने और कीमती अनुभव हासिल करने का मंच देना है। इस टूर्नामेंट में कुल छह टीमें भुवनेश्वर टाइगर्स, पुरी टाइटन्स, क्योंझर माइनर्स, राउरकेला सुपरस्टार्स, संबलपुर वॉरियर्स और कटक पैंथर्स हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट की शुरुआत 20 सितंबर को होगी, जिसमें पहला मैच संबलपुर वॉरियर्स और कटक पैंथर्स के बीच खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता में लीग-स्टेज और नॉकआउट मैच होंगे। प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर रहने वाली टीम को बाराबती स्टेडियम में होने वाले फाइनल में सीधे जगह मिलेगी। इस स्टेडियम में पहले भी इंटरनेशनल मैच हो चुके हैं। दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें क्वालीफायर में एक-दूसरे का सामना करेंगी और जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी। 28 सितंबर को महिलाओं का एक एग्जीबिशन मैच भी खेला जाएगा, जो क्रिकेट फैंस के लिए एक और आकर्षण होगा। **'ओडिशा टी 20 लीग'** लीग 2026 सीएम ट्रॉफी का ग्रैंड फाइनल 29 सितंबर को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दो बेहतरीन टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी।

लीग का ब्रांड एंबेसडर बनने पर सुरेश रैना ने कहा, 'छह टीमें एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबला करेंगी, जिससे 10 दिनों तक रोमांचक और जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगा। यह खिलाड़ियों के लिए अपना हुनर दिखाने और प्रतिस्पर्धी माहौल में खुद को साबित करने का एक शानदार मंच होगा। अपनी तारीखें नोट कर लें और एक ब्लॉकबस्टर टूर्नामेंट के लिए तैयार हो जाएं। जय जगन्नाथ।'

देबाशीष मोहंती ने भी ऐसी ही भावनाएं जाहिर कीं और कहा, 'ओडिशा में क्रिकेट फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। **'ओडिशा टी 20 लीग'** सीएम ट्रॉफी 20 से 29 सितंबर तक कटक के बाराबती स्टेडियम में खेली जाएगी, जिसमें छह टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी। यह टूर्नामेंट हमारे खिलाड़ियों को अपनी स्किल्स दिखाने और दबाव वाले माहौल में खेलने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म देगा। मैं इस टूर्नामेंट को आयोजित करने की कोशिशों के लिए ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूं। मुझे यकीन है कि यह लीग फैंस के लिए बहुत रोमांचक क्रिकेट और यादगार पल लेकर आएगी। मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि वे तारीखें नोट कर लें और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए जरूर आएं। जय जगन्नाथ।'

ओसीए सेक्रेटरी संजय बेहरा ने भी पूर्व भारतीय क्रिकेटरों के जुड़ने का स्वागत करते हुए कहा, **'ओडिशा टी 20 लीग'** सीएम ट्रॉफी के ब्रांड एंबेसडर के तौर पर सुरेश रैना और देबाशीष मोहंती जैसे बेहतरीन भारतीय क्रिकेटरों का जुड़ना सम्मान की बात है। उनके जुड़ने से टूर्नामेंट की अहमियत और बढ़ेगी और ओडिशा के युवा क्रिकेटरों को बड़े सपने देखने और इस प्लेटफॉर्म पर अपना टैलेंट दिखाने की प्रेरणा मिलेगी।'

● एशियन गेम्स 2026 से पहले भारत को झटका

● अन्नू रानी ने 2022 में जीता था स्वर्ण पदक

3 एथलीट भारतीय दल से बाहर

नई दिल्ली। एशियन गेम्स 2026 का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक जापान के आइची-नागोया में होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट से पहले भारत को एक और झटका लगा है। हाल ही में जहां भारत के दो रेसलर डोपिंग के कारण बाहर हो गए थे। वहीं अब तीन स्टार एथलीट भारतीय दल से बाहर हो गए हैं। खास बात यह है कि इन तीन एथलीट में से एक नाम है भारत की स्टार महिला जैवलिन थ्रोअर अन्नू रानी का जिन्होंने 2022 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था।

आपको बता दें पिछली बार की स्वर्ण पदक विजेता अन्नू रानी समेत उभरते हुए लॉन्ग जम्प एथलीट शहनवाज खान और रेसर नित्या गांधे को प्रदर्शन और चिकित्सकीय कारणों के चलते भारत की एशियाई खेलों की एथलेटिक्स टीम से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ ही जापान जाने वाली भारतीय ट्रैक एवं फील्ड टीम की संख्या घटकर 74 रह गई है।

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) ने इससे पहले आगामी एशियाई खेलों के लिए 77 एथलीटों का चयन किया था। बृहस्तिवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज फाइनल के बाद टीम में बदलाव किया गया। इस प्रतियोगिता को अंतिम पुष्टि के लिए चयन ट्रायल के तौर पर आयोजित किया गया था।

एएफआई चयन समिति के अध्यक्ष अदिल सुमरिवाला ने पीटीआई से कहा, 'अन्नू ने बृहस्पतिवार को हुए अंतिम ट्रायल में एएफआई द्वारा निर्धारित क्वालीफाइंग मार्क हासिल नहीं किया, इसलिए उन्हें एशियाई खेलों के लिए नहीं चुना गया।' उन्होंने कहा, 'नित्या और शहनवाज खराब प्रदर्शन और चिकित्सकीय कारणों से एशियाई खेलों में नहीं जाएंगे।'

तीनों खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने का फैसला शुक्रवार को एएफआई चयन समिति की ऑनलाइन बैठक में लिया गया। अब भारतीय एथलेटिक्स टीम के 74 सदस्य शनिवार को नयी दिल्ली से जापान के लिए रवाना होंगे।

सार-समाचार

अमेजन वॉरियर्स ने त्रिनबागो नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया

गुयाना। कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) 2026 का 33वां मुकाबला प्रोविडेंस स्टेडियम में त्रिनबागो नाइट राइडर्स और गुयाना अमेजन वॉरियर्स के बीच खेला गया। अमेजन वॉरियर्स ने अपना शानदार प्रदर्शन बरकरार रखा और त्रिनबागो को 6 विकेट से हरा दिया। अमेजन के लिए शे होप ने नाबाद 42 रन बनाए। अमेजन वॉरियर्स ने जीत के लिए मिले 127 रन के लक्ष्य को 18.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। अमेजन के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज शे होप ने 35

गेंदों पर नाबाद 42 रन की पारी खेली। होप ने जस्टिन ग्रीव्स को चौका और छक्का लगाते हुए मैच खत्म किया। होप ने अपनी पारी में 2 छक्का और 1 चौका लगाया। इसके अलावा, शिमरोन हिटमायर ने 28, मानवेंद्र दिनदयाल ने 19, क्विंटन सैंपसन ने 12 और ग्लेन फिलिप्स ने 11 रन बनाए।

त्रिनबागो के लिए सुनील नरेन ने बेहद किफायती गेंदबाजी की और 4 ओवर में 1 मेडन फेंकते हुए मात्र 13 रन देकर 1 विकेट लिए। उस्मान तारिक ने 4 ओवर में 19 रन देकर 1 और लाहिरु कुमारा ने 4 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट लिए। अकील हुसैन ने भी 4 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट लिया। सुनील नरेन और उस्मान तारिक की किफायती गेंदबाजी भी त्रिनबागो को हार से नहीं बचा सकी। टीम को स्कोर बोर्ड पर कम रन होने का खामियाजा भुगतना पड़ा।

इससे पहले टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने 8 विकेट पर 126 रन बनाए थे। जस्टिन ग्रीव्स ने सबसे ज्यादा 35 रन बनाए। इसके अलावा, सलामी बल्लेबाज कोलिन मुनरो ने 16 गेंदों पर 26, और एलेक्स हेल्स ने 26 गेंदों पर 22 रन बनाए। अकील हुसैन ने 12 और किरोन पोलार्ड ने 10 रन बनाए। गुयाना अमेजन वॉरियर्स की तरफ से मेहदी हसन मिराज ने 4 विकेट लिए। शमार जोसेफ ने 2, जबकि ड्वेन प्रिटोरियस और कप्तान इमरान ताहिर ने 1-1 विकेट लिए।

भारत-श्रीलंका 7वीं बार आज खेलेंगे फाइनल मुकाबला

नई दिल्ली। महिला एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच 13 सितंबर यानी रविवार को खेला जाएगा। महिला एशिया कप के इतिहास में ये 7वां मौका होगा जब खिताबी जीत के लिए भारत और श्रीलंका की टीम आमने-सामने होंगे। इससे पहले भारत और श्रीलंका के बीच 6 बार फाइनल मुकाबले खेले जा चुके हैं जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने इस बार बांग्लादेश और श्रीलंका ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बनाई थी।

7वीं बार खेलेंगे फाइनल

भारत और श्रीलंका के बीच महिला एशिया कप में 7वीं बार फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले दोनों टीमों के बीच 6 फाइनल खेले जा चुके हैं जिसमें से भारत को 5 बार जीत मिली जबकि श्रीलंका ने एक बार भारत के खिलाफ जीत हासिल की थी। भारत और श्रीलंका के बीच 2004, 2005-06, 2006, 2008, 2022 और 2024 फाइनल में भिड़ंत हुई थी जिसमें से भारत ने 2004, 2005-06, 2006, 2008, 2022 के फाइनल में श्रीलंका को हराया था। वहीं श्रीलंका की टीम ने साल 2024 के फाइनल में भारत को हराया था। अब दोनों देश 2026 में एक बार फिर से फाइनल में खेलते हुए नजर आएंगे। इस बार महिला एशिया कप का 10वां सीजन खेला जा रहा है। महिला एशिया कप की शुरुआत 2004 में हुई थी और पिछले 9 सीजन में भारत 7 बार चैंपियन बन चुका है। भारत ने साल 2004, 2005-06, 2006, 2008, 2012, 2016, 2022 में चैंपियन बनने की उपलब्धि अपने नाम की थी।

पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका ने कटाया फाइनल का टिकट

दुबई। विमेंस एशिया कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही श्रीलंका ने फाइनल में जगह बना ली है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका की बल्लेबाजों ने पाकिस्तान से मिले 131 रनों के लक्ष्य को 18.4 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल किया। 131 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान चमारी अटापट्टू 5 रन बनाकर फातिमा सना का शिकार बनीं। संजना कविंदी बिना खाता खोले पवेलियन लौटीं। हसीना परेरा सिर्फ 3 रन ही बना सकीं। इमेशा दुलानी अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाईं और 21 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुईं। हर्षिता समरविक्रमा ने 31 गेंदों का सामना करते हुए 36 रनों की अहम पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 2 चौके लगाए। कविशा दिलहारी ने 33 रनों का योगदान दिया। अंत के ओवरों में नीलाक्षी डी सिल्वा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 10 गेंदों में 3 चौकों की मदद से नाबाद 18 रन बनाए, जबकि कौशानी नुथ्यंगना 4 गेंदों में 10 रन बनाकर नाबाद रहीं। 19वें ओवर की चौथी गेंद पर नीलाक्षी ने फातिमा सना की गेंद पर चौका लगाते हुए श्रीलंका को फाइनल का टिकट दिलाया। इससे पहले, टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही।

यूएस ओपन: करेन खाचानोव को दी मात

अलेक्जेंडर ज्वेरेव फाइनल में पहुंचे

न्यूयॉर्क। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने यूएस ओपन 2026 एकल के फाइनल में जगह बना ली है। ज्वेरेव ने सेमीफाइनल में करेन खाचानोव को 6-3, 7-6(7), 7-6(6) से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। मैच की शुरुआत में ज्वेरेव नियंत्रण में दिख रहे थे। उनकी सर्व ने उन्हें एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म दिया, जबकि उनके बेसलाइन गेम ने खाचानोव को बार-बार असहज स्थिति में डाला।

रूसी खिलाड़ी के 3-3 से बराबर होने के बाद, ज्वेरेव ने अहम मौके पर अपनी तेजी बढ़ाई ताकि उन्हें जरूरी एकमात्र ब्रेक मिल सके और पहला सेट जीत सकें। खाचानोव ने दूसरे सेट में जोरदार जवाब दिया। ज्वेरेव शुरू में 2-0 से आगे हो गए, लेकिन रूसी खिलाड़ी को दोनों विंग से ज्यादा आक्रामकता मिली और उन्होंने सेट पलट दिया। वह 5-4 से आगे हो गए और ज्वेरेव पर दबाव डाला, इससे पहले कि जर्मन खिलाड़ी ने मजबूती से टिककर टाई-ब्रेक के लिए मजबूर किया।

टाई-ब्रेक हिम्मत का टेस्ट बन गया। ज्वेरेव ने दो सेट पॉइंट गंवाए लेकिन अपने तीसरे मौके का फायदा उठाकर फाइनल से एक सेट के अंदर पहुंच गए। खाचानोव ने मैच

का अपना सबसे अच्छा टेनिस खेला था, फिर भी ज्वेरेव ने दबाव वाले क्षणों में भी धैर्य से खेल बढ़ाया। तीसरा सेट भी छोटे-छोटे अंतरों की लड़ाई थी। ज्वेरेव पहले 5-4 और बाद में 6-5 से आगे थे। लेकिन खाचानोव ने दोनों बार गेम बनाए रखा और एक और टाई-ब्रेक के लिए मजबूर किया।

'मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती', वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर एक का ताज छीनने के बाद बोलीं सबालेंका

न्यूयॉर्क। एलेना रिबाकिना विश्व की नंबर एक महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने बेलारूस की आर्यना सबालेंका की बादशाहत को खत्म करते हुए नंबर एक की कुर्सी हासिल की। सबालेंका ने नंबर एक की पोजीशन गंवाने के बाद कहा कि वह इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हैं। एलेना रिबाकिना और आर्यना सबालेंका रविवार को यूएस ओपन 2026 के महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबले में भिड़ेंगी। दोनों के बीच यह मुकाबला आर्थर ऐश स्टेडियम में खेला जाएगा। सबालेंका ने कहा कि दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनना बिल्कुल आसान नहीं है। उन्होंने माना कि सीजन के बीच में उनका प्रदर्शन थोड़ा गिर गया था, लेकिन नंबर एक की पोजीशन को गंवाना उन्होंने थोड़ा अजीब बताया। सेमीफाइनल में जेसिका पेगुला को हराने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, 'मैं अच्छी तरह समझती हूं कि वर्ल्ड नंबर 1 तक पहुंचना कितना मुश्किल है।

कॉनर एस्टरहुइजेन ने खेली शतकीय पारी

साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे में नामीबिया को 157 रनों से रौंदा

नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका ने नामीबिया को दूसरे वनडे मुकाबले में 157 रनों से रौंदा। साउथ अफ्रीका से मिले 336 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए नामीबिया की पूरी टीम 178 रन बनाकर ऑलआउट हुई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी नामीबिया की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज माइकल वैन लिंगेन और मालन क्रूगर बिना खाता

खोले पवेलियन लौटे। वहीं, जेन फ्रीलिंक भी बिना कोई रन बनाए आउट हुए। लॉरेन स्टीनकैंप भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और वह 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जैन निकोल लॉफ्टी-ईटन भी महज 6 रन बनाकर आउट हुए। नामीबिया की टीम महज 32 के स्कोर पर 5 विकेट गंवाकर मुश्किल में दिख रही थी। हालांकि, जेन ग्रीन ने कप्तान गेरहार्ड इरास्मस का साथ देने का प्रयास किया और छठे विकेट के लिए 27 रन जोड़े। ग्रीन 11 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद जैन बाल्ट ने सातवें विकेट के लिए इरास्मस संग मिलकर 71 रनों की साझेदारी निभाई। बाल्ट 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

इरास्मस ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 84 गेंदों में 68 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 6 चौके और एक छक्का लगाया। रुबेन ट्रम्पेलमैन ने 27 गेंदों में 30 रन बनाए, जबकि वाल्डो स्मिथ ने 10 रनों का योगदान दिया। साउथ अफ्रीका की ओर से डुआन जानसेन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 31 रन देकर 4 विकेट चटकाए। वहीं, ईथन बॉश ने 3 विकेट अपने नाम किए।

इससे पहले, साउथ अफ्रीका की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही और जॉर्डन हरमन 24 गेंदों में 20 रन बनाने के बाद आउट हुए। हालांकि, इसके बाद कॉनर एस्टरहुइजेन और टोनी डी जोर्जी ने मोर्चा संभाला और दूसरे विकेट के लिए 168 गेंदों में 183 रन जोड़े। टोनी जोर्जी ने 87 गेंदों में 6 चौके और एक छक्के की मदद से 79 रन बनाए।

संक्षिप्त समाचार

तपती धरती, उबलते समंदर: अगस्त बना इतिहास का सबसे गर्म महीना, पूर्वी यूरोप में गंभीर सूखे की स्थिति; आगे क्या

जेनेवा, एजेंसी। वैश्विक स्तर पर जलवायु संकट ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। यूरोपीय संघ की प्रमुख निगरानी संस्था कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस (सी3एस) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2026 जुलाई 2023 के साथ संयुक्त रूप से इतिहास का सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया है। इस दौरान दुनिया का औसत वायु तापमान 16.96 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 1991-2020 के औसत से 0.85 डिग्री सेल्सियस और पूर्व-औद्योगिक काल (1850-1900) की तुलना में 1.65 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वैज्ञानिकों के अनुसार, यह अप्रत्याशित गर्मी जीवाश्म ईंधन (कोयला, तेल, गैस) के जलने से वायुमंडल में लगातार बढ़ रही ग्रीनहाउस गैसों और भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में सक्रिय हो रही मजबूत अल नीनो परिस्थितियों का मिला-जुला नतीजा है। महासागरों का तापमान भी रिकॉर्ड स्तर पर है। 60 डिग्री दक्षिण से 60 डिग्री उत्तर के बीच गैर-ध्रुवीय महासागरों का औसत सतही तापमान 21.07 डिग्री दर्ज किया। इसने अगस्त 2023 में बने 20.98 डिग्री के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। पश्चिमी यूरोप ने अपने इतिहास की सबसे भीषण गर्मी का सामना किया, जिसने 2003 के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। मई महीने से शुरू हुआ भीषण लू का सिलसिला अगस्त तक जारी रहा। गर्मी के साथ पश्चिमी, मध्य और पूर्वी यूरोप के बड़े हिस्से में गंभीर सूखे की स्थिति बन गई।

अमेरिकी थिंकटैंक एफएएस की रिपोर्ट 160+ हथियार तैयार किए जा चुके; 730 किलो प्लूटोनियम मौजूद; और क्या खास

वाशिंगटन, एजेंसी। भारत के परमाणु शस्त्रागार में अनुमानित रूप से 190 एटमी हथियार हैं, जिनमें नई मिसाइलों के लिए तैयार किए जा रहे 30 अतिरिक्त हथियार भी शामिल हैं। यही नहीं, उसके पास करीब 35 परमाणु हथियार तैयार करने लायक प्लूटोनियम भी रिजर्व भंडार में है। यह बात अमेरिका के एक गैर-सरकारी थिंकटैंक फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स (एफएएस) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कही है। एफएएस ने यह अनुमान ओपन सोर्स पर उपलब्ध जानकारी, सरकारी डाटा और कमर्शियल सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के विश्लेषण के आधार पर लगाया है। एफएएस के न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के निदेशक हंस क्रिस्टेनसेन के बुधवार को प्रकाशित लेख में कहा गया है कि भारत अपने परमाणु शस्त्रागार को लगातार आधुनिक बना रहा है। एफएएस के मुताबिक, 2026 की शुरुआत तक इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल्स का अनुमान था कि भारत ने लगभग 730 किलोग्राम हथियार-ग्रेड प्लूटोनियम का उत्पादन किया है। यह सैद्धांतिक रूप से 140 से 225 के बीच परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त होगा। लेख में कहा गया, भारत करीब 190 हथियार असेंबल कर चुका है। लेकिन यह सिर्फ अनुमानित संख्या है, क्योंकि हथियार में कितना प्लूटोनियम इस्तेमाल होगा, यह काफी हद तक उसके डिजाइन पर निर्भर करता है। एफएएस के मुताबिक, भारत जमीन, हवा और समुद्र तीनों माध्यमों से परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित कर रहा है।

नेपाल में बाढ़ के बाद 70 अमेरिकी नागरिक अभी भी लापता, 18 बचाए गए; त्रासदी पर क्या बोला विदेश विभाग

वाशिंगटन, एजेंसी। नेपाल-चीन सीमा क्षेत्र में आई भीषण आपदा के बाद करीब 70 अमेरिकी नागरिक अब भी लापता हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि आपदा में सड़कें और पुल तबाह हो गए हैं, जबकि कई पूरे गांव भी मलबे में दब गए हैं। विदेश विभाग के मुताबिक, गुरुवार दोपहर तक 18 अमेरिकी नागरिक सुरक्षित स्थानों पर पहुंच चुके हैं। विभाग ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि काठमांडू में मौजूद अमेरिकी टीम नेपाल पहुंचे सभी प्रभावित परिवारों से मिल चुकी है। वहीं, वॉशिंगटन में तैनात अधिकारी अमेरिका में मौजूद परिवारों के साथ लगातार संपर्क में हैं।प्रवक्ता ने बताया कि राहत और बचाव दलों के लिए हालात बेहद मुश्किल हैं। आपदा में सड़कें, पुल और पूरे गांव नष्ट हो गए हैं। कई इलाकों का नक्शा ही बदल गया है। कुछ जगहों पर पहले जहां लोग रहते थे, वहां अब कई फीट तक मिट्टी और चट्टानों का मलबा जमा है। आपदा के कारण हेलीकॉप्टर से चलाए जा रहे राहत और बचाव अभियान में भी मुश्किलें आ रही हैं। पायलटों को संकरी घाटियों से उड़ान भरनी पड़ रही है।

9/11 के 25 साल: वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले के बाद कैसे बदली दुनिया अमेरिका में नहीं हुआ फिर बड़ा आतंकी हमला

वाशिंगटन, एजेंसी। एक ऐसा हमला, जिसने कुछ घंटों में अमेरिका की तस्वीर बदल दी। दिन था 11 सितंबर 2001। आतंकवादियों ने चार विमानों को हाईजैक कर कई ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें से दो विमानों को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ट्विन टावर से टकराया। वहीं एक विमान पेंटागन से जा टकराया। चौथा विमान पेंसिल्वेनिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हमले में हजारों लोगों की जान चली गई।

घटना के 25 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उस दिन की दर्द आज भी लोगों के जेहन में ताजा हैं। इस हमले के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति में बड़े बदलाव किए। दुनिया के कई देशों ने भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया। आइए जानतें हैं कि अमेरिका ने पिछले 25 वर्षों में ऐसा क्या किया, जिसके बाद वहां कभी भी कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। अमेरिका ने क्या बड़े बदलाव किए हैं इसके साथ ही भारत को इससे क्या सीखना चाहिए

आतंकवाद और चरमपंथ से लड़ने के लिए क्या किया : आतंकी हमलों के बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दुनिया भर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान शुरू करने का एलान किया। इसे 'ग्लोबल वॉर ऑन टेरर' (त्ङ्ख्ह्ञ) कहा गया। इसमें सैन्य कार्रवाई के साथ आतंकियों की आर्थिक मदद रोकना शामिल था।

इसके साथ ही उन्हें सुरक्षित ठिकाने मिलने से रोकना भी शामिल था। कई देशों ने इस अभियान में अमेरिका का साथ दिया। 20 सितंबर 2001 को बुश ने तालिबान से अल-कायदा के सदस्यों को पनाह देना बंद करने को कहा। इसके बाद 24 सितंबर को आतंकवादी संगठनों और उन्हें आर्थिक मदद देने वालों की संपत्तियां फ्रीज करने का आदेश दिया गया। 7 अक्तूबर 2001 को अमेरिका ने अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई शुरू की। शुरुआती हमलों में अल-कायदा के प्रशिक्षण शिविरों और तालिबान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके साथ अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय मदद भी देने की बात कही गई। इसके बाद अमेरिका ने इराक पर भी दबाव बढ़ाया। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की सरकार पर आतंकवाद से संबंध और बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियार रखने जैसे आरोप लगाए। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक में सैन्य अभियान शुरू किया, जिसका मकसद सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाना था।

डीएचएस का मुख्य मकसद क्या है : डीएचएस का मुख्य मकसद देश को आतंकवाद और दूसरे सुरक्षा खतरों से बचाना था। इसके तहत अलग-अलग सरकारी एजेंसियों को एक साथ लाया गया, ताकि उनके बीच बेहतर तालमेल हो सके। कुल 22 एजेंसियों और कार्यालयों को मिलाकर एक कैबिनेट स्तर का विभाग बनाया गया। टॉम रिज इसके पहले सचिव बने।

डीएचएस को क्यों आलोचना का सामना करना पड़ा : हालांकि, शुरुआत में डीएचएस को कामकाज में तालमेल की कमी और नौकरशाही जैसी समस्याओं को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा। 2005 में आए तूफान कैटरीना के दौरान भी इसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठे। इसके अलावा निगरानी और नागरिक अधिकारों को लेकर भी चिंताएं सामने आईं। डीएचएस ने लोगों को आतंकवादी खतरों के बारे में जानकारी देने के लिए सुरक्षा चेतावनी प्रणाली शुरू की, जिसे बाद में 2011 में नेशनल टेररिज्म एडवाइजरी सिस्टम से बदल दिया गया। इसका उद्देश्य आतंकवाद से निपटने के साथ देश की आपदा और आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करना था।

यूएसए पेट्रियट एक्ट 26 अक्टूबर 2001 को 9/11 आतंकी हमलों के बाद लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका की घरेलू सुरक्षा को मजबूत करना और आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच को आसान बनाना था। इस कानून के तहत सुरक्षा और जांच एजेंसियों को आतंकवाद की रोकथाम और जांच के लिए कई अधिकार दिए गए। कानून के तहत आतंकवाद से जुड़े मामलों में निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने की प्रक्रिया को मजबूत किया गया। अलग-अलग पुलिस, खुफिया और जांच एजेंसियों के बीच जानकारी साझा करने के रास्ते भी आसान किए गए। इसका मकसद यह था कि किसी संभावित आतंकी साजिश की जानकारी समय रहते मिल सके और उस पर कार्रवाई की जा सके। पेट्रियट एक्ट में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए होने वाली आर्थिक मदद पर रोक लगाने के लिए भी कई प्रावधान किए गए। 10 हजार डॉलर से ज्यादा की नकदी को अवैध तरीके से अमेरिका के अंदर या बाहर ले जाने पर नए नियम और सजा का प्रावधान किया गया।साइबर अपराध और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर संभावित आतंकी हमलों से निपटने के लिए भी एजेंसियों को अतिरिक्त अधिकार दिए गए।

मिस्टर सिंह' वाले विज्ञापन पर मचा बवाल, सरकार ने हटाया पोस्ट; क्यों हुआ इतना विरोध

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने गुरुवार को एक विवादित विज्ञापन हटा दिया। इसमें 'मिस्टर सिंह' से अमेरिका छोड़ने के लिए कहा गया था। भारतीय मूल अमेरिकियों के संगठनों और डेमोक्रेटिक नेताओं ने इसका विरोध किया था। उन्होंने इसे नस्लवादी प्रचार बताया था।

गृह सुरक्षा विभाग ने बिना लाइसेंस वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ यह अभियान शुरू किया था। इसी अभियान के तहत यह विज्ञापन जारी किया गया था। इसके लिए एक्स पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से बनाई गई तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। तस्वीर में दाढ़ी वाला एक सांवले रंग का व्यक्ति दिखाया गया था। उसके साथ लिखा था- हमारी सड़कों से हट जाओ, मिस्टर सिंह, तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता।

विरोध क्यों हुआ : इस विज्ञापन का भारतीय-अमेरिकी और सिख संगठनों ने जोरदार विरोध किया। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम और सांसद राजा कृष्णमूर्ति जैसे डेमोक्रेट नेताओं ने भी इसका विरोध किया। न्यूसम के प्रेस कार्यालय ने एक्स पर कहा, यह घिनौना है। ट्रंप सरकार सिख समुदाय को निशाना बनाकर नस्लवादी प्रचार कर रही है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, सिख कोएलिशन, हिंदू एक्शन और कोएलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका जैसे संगठनों ने भी विज्ञापन को अमेरिकी मूल्यों के खिलाफ और नस्लवादी बताया। गृह

सुरक्षा विभाग ने विवादित विज्ञापन तो हटा दिया। लेकिन उसने न्यूसम पर पलटवार किया। विभाग ने उन पर अवैध प्रवासियों को व्यावसायिक वाहन चलाने के लाइसेंस देने का आरोप लगाया। न्यूसम को 2028 के राष्ट्रपति चुनाव का संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है।

भारतीय समुदाय के संगठनों ने क्या कहा : भारतीय समुदाय के संगठनों ने विज्ञापन हटाने का स्वागत किया। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने कहा कि गृह सुरक्षा विभाग ने वह पोस्ट हटा दी है, जिस पर संगठन ने एक दिन पहले आपत्ति जताई थी। हालांकि, संगठन ने कहा कि किसी संघीय एजेंसी का भारतीय या सिख व्यक्ति का नस्लीय रूप दिखाकर राजनीतिक संदेश देना गंभीर बात है। पोस्ट हटाना केवल पहला कदम है। संगठन ने कहा कि भारतीय-अमेरिकी, सिख, हिंदू और दक्षिण एशियाई लोगों को अपनी सरकार से इससे बेहतर व्यवहार की उम्मीद है। विभाग ने ट्रक चालक हरजिंदर सिंह का एक वीडियो भी पोस्ट किया। हरजिंदर सिंह को पिछले साल एक गैरकानूनी यू-टर्न के कारण हुए हादसे के बाद गिरफ्तार किया गया था।

अवैध प्रवासी को अदालत से बाहर जाने देने के आरोप में जज पर कार्रवाई; आठ साल पुराने मामले में क्या हुआ

बोस्टन, एजेंसी। अमेरिका के मैसाचुसेट्स की सबसे बड़ी अदालत ने गुरुवार को जिला अदालत की जज शेली जोसेफ को सार्वजनिक रूप से कड़ी फटकार लगाई। उन पर आरोप था कि उन्होंने एक प्रवासी को अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन की हिरासत से भागने में मदद की थी। यह मामला 2018 का है। उस समय जज शेली जोसेफ पर आरोप लगा था कि उन्होंने अप्रवासी के वकील और अदालत के एक अधिकारी के साथ मिलकर उसे भागने दिया। आरोप था कि सुनवाई के बाद उसे अदालत की इमारत के पिछले दरवाजे से बाहर निकलने दिया गया। उस पर नशीली दवाएं रखने समेत कई आरोप थे। सर्वोच्च न्यायिक अदालत ने यह फैसला न्यायिक आचरण आयोग के सुनवाई अधिकारी की सिफारिश के बाद दिया। आयोग ने माना था कि जोसेफ के काम से गलत आचरण का आभास हुआ। उन्होंने कानून का भी पालन नहीं किया। अदालत के फैसले के मुताबिक, जोसेफ ने प्रवासी को रातभर राज्य की हिरासत में रखने का सुझाव दिया था। उन्होंने अदालत के लिपिक को सुनवाई की आवाज रिकॉर्ड करने वाली व्यवस्था बंद करने का निर्देश भी दिया था। अदालत ने कहा कि इन कामों से गलत आचरण का आभास हुआ और यह उनके न्यायिक कर्तव्यों के खिलाफ था। जोसेफ की वकील एलिजाबेथ मुलवे ने पिछले साल आयोग की सुनवाई में कहा था कि समय के साथ इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। लोगों को लगने लगा कि उनकी मुवक्किल ने 'एक अवैध अप्रवासी को दरवाजे से बाहर जाने दिया'। उनके मुताबिक, कुछ लोग जोसेफ को जेल भेजने की बात कर रहे थे। वहीं कुछ लोग उन्हें 'जनता की नायिका' बता रहे थे। मुलवे ने कहा कि जोसेफ को मीडिया में बदनाम किया गया। लोग ऐसा दिखा रहे थे, जैसे दर्जनों लोगों ने जोसेफ को जज की कुर्सी से उठकर जाते हुए देखा हो। इसके बाद वह आरोपी को दरवाजे तक ले गई हो। उसे गले लगाया और सुरक्षित यात्रा की शुभकामना दी।

चार्ली किर्क की पहली बरसी: यूएस में राष्ट्रपति के करीबी को श्रद्धांजलि, ट्रंप क्या बोले 2025 में हुई थी हत्या

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन मिडटर्म सम्मेलन के दूसरे दिन गुरुवार को रिपब्लिकन नेताओं और समर्थकों ने 'टर्निंग पॉइंट यूएसए' के संस्थापक चार्ली किर्क को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूरा हॉल 'चार्ली, चार्ली' के नारों से गूंज उठा। बता दें कि एक साल पहले किर्क की हत्या कर दी गई थी। डलास के बास्केटबॉल स्टेडियम में जुटी भीड़ उस समय एकदम खामोश हो गई, जब किर्क के सम्मान में पांच मिनट का एक स्मृति वीडियो दिखाया गया। इस वीडियो ने सम्मेलन के सियासी माहौल को कुछ देर के लिए पूरी तरह गमगीन कर दिया। ट्रंप वॉर रूम नाम के ट्रुथ सोशल हैंडल पर किर्क को महान बताया गया। ट्रंप ने इस संदेश और वीडियो को रिपोस्ट किया।

क्या बोले टर्निंग पॉइंट के उपाध्यक्ष : इस दौरान टर्निंग पॉइंट के उपाध्यक्ष और पादरी लुकास माइल्स ने कहा कि एक साल बीत जाने के बाद भी चार्ली किर्क की आवाज कमजोर नहीं पड़ी है। उन्होंने बताया कि इस एक साल में संगठन के सदस्यों और सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। माइल्स ने सम्मेलन में कहा- टर्निंग पॉइंट खत्म नहीं हुआ है। चार्ली ने जिस संस्था की नींव रखी थी, वह लगातार बढ़ रही है और अब एक नई पीढ़ी आगे आ रही है। चार्ली किर्क अमेरिकी दक्षिणपंथ में एक बेहद असरदार चेहरा थे। उन्होंने कॉलेज परिसरों में युवाओं का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया, एक चर्चित पॉडकास्ट चलाया और युवा रूढ़िवादी ईसाइयों के बीच गहरी पकड़ बनाई। वह डोनाल्ड ट्रंप के 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' अभियान के अलग-अलग गुटों को एकजुट रखने वाले एक अहम सूत्रधार भी थे।

किर्क की हत्या 10 सितंबर 2025 को यूटा वैली यूनिवर्सिटी कैंपस में उस समय कर दी गई थी, जब वह छात्रों को संबोधित कर रहे थे। मामले में 23 साल के टायलर रॉबिन्सन पर हत्या का गंभीर आरोप है और दोष साबित होने पर उसे मौत तक की सजा मिल सकती है। उसने घटना के अगले दिन खुद सरेंडर कर दिया था, हालांकि अदालत में उसने खुद को बेकसूर बताया है। किर्क की मौत के बाद संगठन में आंतरिक खींचतान भी देखने को मिली है। जानी-मानी पॉडकास्टर कैंडिस ओवेन्स समेत कई लोगों ने सरकारी वकीलों की इस थ्योरी पर सवाल उठाए हैं कि हत्या में सिर्फ रॉबिन्सन ही शामिल था। इसे लेकर इंटरनेट पर भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं।

अब किर्क की पत्नी एरिका किर्क को टर्निंग पॉइंट की नई सीईओ बनाया गया है, जो अब सार्वजनिक भाषणों का जिम्मा संभाल रही हैं। साथ ही डिबेट कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए अन्य विश्लेषकों को भी मंच दिया जा रहा है। संगठन ने यूटा के ओरेम स्थित उस यूनिवर्सिटी कैंपस में भी एक शोक सभा रखी, जहां किर्क की हत्या हुई थी। संगठन ने अपने बयान में कहा कि किर्क की कमी आज भी महसूस की जा रही है।

ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट में गहराया संकट: लगातार दूसरी बैठक रद्द, जजों पर भ्रष्टाचार के मामले में बढ़ा विवाद

ब्रासीलिया, एजेंसी। ब्राजील के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को लगातार दूसरे दिन की सुनवाई रद्द कर दी। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब देश में राजनीतिक और संस्थागत संकट गहराता जा रहा है। कोर्ट के कई सदस्यों पर भ्रष्टाचार, राजनीतिक पक्षपात और पुलिस के काम में दखल देने के आरोपों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस विवाद का असर अक्टूबर में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों पर भी पड़ रहा है।

चीफ जस्टिस लुइज एडसन फाचिन ने गुरुवार की बैठक टालते हुए मंगलवार को अगली बैठक तय की है, जबकि आमतौर पर मंगलवार को कोर्ट की ऐसी बैठक नहीं होती।

मंगलवार को सभी 10 जजों की बेंच इस बात पर फैसला करेगी कि क्या उनके ही एक साथी जज अलेक्जेंड्रे डी मोरेस के खिलाफ जांच होनी चाहिए। मोरेस पर धोखाधड़ी के आरोपों के बाद बंद हो चुके 'बैंको मास्टर' के मालिक के साथ कथित संबंधों का आरोप है।

सुप्रीम कोर्ट में यह विवाद 1 सितंबर को तब बढ़ा, जब पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के कार्यकाल में नियुक्त हुए जज आंद्रे मेंडोंका ने फेडरल पुलिस के गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक किए। इन दस्तावेजों के मुताबिक, बैंक मालिक डेनियल वोर्कारो ने कानूनी सलाह के लिए कई बार जज मोरेस से संपर्क किया था। इसके बाद से ही मोरेस और मेंडोंका के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। मोरेस को उस समय मौजूदा राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा के समर्थकों ने बहुत सराहा था, जब उन्होंने पिछले साल तख्तापलट की साजिश रचने के जुर्म में पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को 27 साल की जेल की सजा सुनाई थी। दूसरी तरफ, मेंडोंका सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले बोल्सोनारो की सरकार में सॉलिसिटर-जनरल रह चुके हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में डी मोरेस ने भी जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने मेंडोंका के खिलाफ कथित तौर पर अधिकारों के दुरुपयोग की जांच की मांग की। मामला बैंकर से हुई एक बातचीत से जुड़ा है, जिसमें पुलिस या अभियोजकों की मौजूदगी नहीं थी।

इस कानूनी जंग ने ब्राजील की राजनीति में भी भूचाल ला दिया है। राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा और आगामी चुनाव में उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी यानी पूर्व राष्ट्रपति के बेटे सीनेटर फ्लेवियो बोल्सोनारो, दोनों अपने-अपने राजनीतिक नफे-नुकसान को देखते हुए जजों के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं।

जेल में बिगड़ी मादुरो की पत्नी की सेहत: 11 किलो वजन घटा; दिल की बीमारी के बीच घर में नजरबंदी की मांग क्यों

अल्बानी, एजेंसी। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की पत्नी और देश की पूर्व प्रथम महिला सीलिया फ्लोरेस ने अमेरिका की अदालत से जेल से बाहर आने की मांग की है। 69 वर्षीय फ्लोरेस इस समय ब्रुकलिन की संघीय जेल में बंद हैं। उनके वकीलों ने कहा है कि जेल में रहने के दौरान उनकी दिल की बीमारी और बिगड़ गई है। इसलिए उन्हें मुकदमे की सुनवाई तक जेल के बजाय घर में नजरबंद रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। फ्लोरेस के वकीलों ने बुधवार को अदालत में आवेदन दिया है। उन्होंने मैनहट्टन संघीय अदालत के क्षेत्र में घर में रखने की मांग की। अगले साल जून में फ्लोरेस और मादुरो का मुकदमा होना है। घर में रहने के दौरान 24 घंटे सशस्त्र निगरानी की बात कही गई है।

घर में नजरबंदी की स्थिति में फ्लोरेस पर कैसी पाबंदियां रहेंगी : वकीलों मार्क डोनेली और एंड्रेस सांचेज ने अदालत को बताया कि घर में रहने की अनुमति मिलने पर फ्लोरेस की कड़ी निगरानी की जाएगी। उनके मुताबिक, उन्हें 24 घंटे सशस्त्र सुरक्षा में रखा जाएगा। उनसे मिलने वाले लोगों को अदालत और संघीय अभियोजकों से मंजूरी लेनी होगी। घर में वीडियो के जरिये निगरानी होगी और उनके फोन कॉल रिकॉर्ड किए जाएंगे। यानी वकील जेल से बाहर आने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह खुली आजादी नहीं।

फ्लोरेस कई वर्षों से माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स नाम की दिल की बीमारी से जूझ रही हैं। वकीलों का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद से उन्हें इस बीमारी को संभालने के लिए जरूरी मासिक इंजेक्शन नहीं मिला है। इसके बजाय उन्हें बेबी एस्पिरिन, स्टैटिन और डिल्टियाजेम

दी जा रही हैं, जबकि सीने में दर्द होने पर नाइट्रोग्लिसरीन लेने को कहा गया है। फ्लोरेस लगातार रिफ्लक्स और गैस्ट्राइटिस से भी परेशान हैं। जेल में रहते हुए उनके दो दांत निकल चुके हैं। उनका वजन 11.3 किलोग्राम से ज्यादा कम हो गया है। डॉक्टरों ने उन्हें कार्डियक कैथेटराइजेशन कराने की सलाह दी है। फ्लोरेस और उनके पति निकोलस मादुरो को जनवरी की शुरुआत में काराकास स्थित उनके घर से अमेरिकी बलों ने आधी रात की कार्रवाई में हिरासत में लिया था। इसके बाद दोनों को न्यूयॉर्क लाया गया। अमेरिका ने दोनों पर कोकीन को अमेरिका पहुंचाने की साजिश में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। दोनों ने इन आरोपों में खुद को निर्दोष बताया है। अलग अदालत में दाखिल एक याचिका में दोनों ने अपने खिलाफ आरोपपत्र खारिज करने की मांग भी की है। उनका कहना है कि किसी विदेशी देश के नेता और प्रथम महिला होने के कारण उन्हें कानूनी छूट यानी इम्युनिटी हासिल है। अभी अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने फ्लोरेस की घर में नजरबंदी की मांग पर जवाब दाखिल नहीं किया है। मैनहट्टन स्थित अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के प्रवक्ता ने भी टिप्पणी करने से इनकार किया है।

पुतिन का प्लेन नहीं, कमांड सेंटर: किसमें हैं रूसी राष्ट्रपति पहचानना मुश्किल; क्यों साथ उड़ते हैं दो विमान

मॉस्को, एजेंसी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे हैं। लेकिन उनकी यात्रा में सिर्फ कूटनीतिक मुलाकातें ही चर्चा में नहीं हैं। उनके भारत आने के तरीके ने भी लोगों का ध्यान खींचा है। पुतिन जिस खास विमान से यात्रा करते हैं, उसकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी गोपनीय रखी जाती है कि बाहर से यह पता लगाना मुश्किल होता है कि राष्ट्रपति आखिर किस विमान में सवार हैं। हाल की रिपोर्टों में उनके विमान को 'फ्लाइंग क्रेमलिन' भी कहा गया है।

इस यात्रा के दौरान खास बात यह रही कि पुतिन के साथ एक जैसा दूसरा विमान भी उड़ता दिखाई दिया। दोनों का मॉडल, रंग और बाहरी डिजाइन एक जैसा था। यानी आसमान से देखने वाले के लिए दोनों में अंतर करना आसान नहीं था। यही पूरी सुरक्षा रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है।

दो एक जैसे विमान क्यों उड़ते हैं पुतिन के साथ : रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को से आईएल-96-300पीयू मॉडल के दो एक जैसे विमानों के साथ भारत के लिए उड़ान भरी। इनमें से एक विमान में राष्ट्रपति होते हैं, जबकि दूसरा डिकॉय विमान के तौर पर साथ उड़ता है। इसका मकसद यह भ्रम बनाए रखना है कि पुतिन वास्तव में किस विमान में मौजूद हैं।

डिकॉय फ्लाइट की रणनीति ऐसे समझें: दोनों विमान एक ही मॉडल के होते हैं और उनका रंग-रूप भी एक जैसा रखा जाता है, ताकि बाहर से पहचान करना मुश्किल रहे। दोनों विमान एक साथ उड़ान भरते हैं और पुतिन इनमें से किसी एक में होते हैं, लेकिन कौन से विमान में हैं, यह सार्वजनिक तौर पर पता नहीं चलता। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यही है कि किसी संभावित हमलावर के लिए पहले यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि राष्ट्रपति किस विमान में यात्रा कर रहे हैं। राष्ट्रपति के विमान की वास्तविक पहचान की जानकारी उनकी सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों तक ही सीमित रहती है।

क्या रडार पर भी दोनों विमानों को लेकर भ्रम पैदा किया जाता है :

दी गई जानकारी के मुताबिक, सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ दो एक जैसे विमान उड़ाने तक सीमित नहीं है। दोनों विमानों के रडार सिग्नल में भी समय-समय पर बदलाव होता है। कभी एक विमान का सिग्नल बंद दिखाई देता है तो कभी दूसरे का। कुछ समय के लिए दोनों विमान ट्रैकिंग सिस्टम पर दिखाई नहीं देते। यही वजह है कि केवल सार्वजनिक फ्लाइट ट्रैकिंग के आधार पर यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि पुतिन किस विमान में हैं। इस तरह की डिकॉय ड्रिल पहले भी उनकी यात्राओं में दिखाई दे चुकी है।

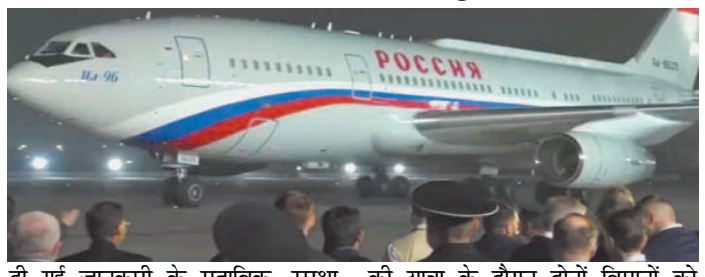

कजाकिस्तान यात्रा में भी दिखी थी ऐसी ही रणनीति : कजाकिस्तान की यात्रा के दौरान दोनों विमानों को फ्लाइट ट्रैकर पर एक-दूसरे के बेहद करीब उड़ते देखा गया था। दोनों विमान लगभग एक ही गति से उड़ रहे थे, जिससे यह पहचानना और मुश्किल हो गया कि राष्ट्रपति किस विमान में हैं।

उस समय दोनों विमानों की पहचान आरएसडी221 और आरएसडी369 के तौर पर हुई थी। इसके बावजूद सार्वजनिक ट्रैकिंग से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि पुतिन इनमें से किस विमान में सवार थे।

पुतिन का आईएल-96-300पीयू विमान आम विमान से कितना अलग : पुतिन का विमान आईएल-96-300पीयू सामान्य यात्री विमान का साधारण रूप नहीं है। यह आईएल-96-300 का विशेष रूप से तैयार किया गया संस्करण है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पीयू का इस्तेमाल रूसी राष्ट्रपति के विशेष विमान के तौर पर होता है। इस विमान की सबसे महत्वपूर्ण खासियत उसकी सुरक्षित संचार व्यवस्था बताई जाती है।

इसमें सैटेलाइट फोन और ऐसी विशेष संचार सुविधाओं का जिक्र है, जिनकी मदद से राष्ट्रपति यात्रा के दौरान भी रूस से संपर्क में रह सकते हैं। विमान को मिसाइल हमले से बचाने के लिए विशेष सुरक्षा उपकरणों से लैस बताया गया है। इसी वजह से इसे आम राष्ट्रपति विमान से कहीं ज्यादा सुरक्षित और विशेष विमान माना जाता है। विमान में सैटेलाइट फोन और विशेष संचार व्यवस्था मौजूद होने की जानकारी दी गई है, ताकि यात्रा के दौरान भी संपर्क बना रहे। इसमें मिसाइल हमले से बचाने वाली विशेष सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र है, जो विमान की सुरक्षा को मजबूत बनाती है।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

हवा में फेल हुआ अलायंस एयर का इंजन, दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग, सभी सवार 40 यात्री सुरक्षित

नई दिल्ली (एजेंसी)। अलायंस एयर की एक फ्लाइट का इंजन हवा में खराब हो जाने के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (आईजीआईए) पर उसकी आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। इस घटना में विमान में सवार क्रू मेंबर्स सहित सभी 40 लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। अलायंस एयर की फ्लाइट संख्या ने दोपहर करीब 12:33 बजे प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान के दौरान, जब विमान मेरठ के आसपास था, पायलट को एक इंजन में तकनीकी खराबी का पता चला। स्थिति की गंभीरता को देखकर पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को इसकी सूचना दी और दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। सूचना मिलते ही आईजीआईए पर तत्काल आपातकाल घोषित किया। टर्मिनल-1 के रनवे-4 पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की गईं। लगभग 30 मिनट तक रनवे को पूरी तरह से खाली रखा गया। विमान ने अपने दूसरे इंजन की मदद से दोपहर करीब 2:15 बजे सफलतापूर्वक और सुरक्षित लैंडिंग की। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने गंभीर तकनीकी खराबी की जांच के आदेश दे दिए हैं। यह वही विमान था जो सुबह बिलासपुर से प्रयागराज पहुंचा था और कुछ देर बाद दिल्ली के लिए रवाना हुआ था।

गोमती पुस्तक महोत्सव शुरू : सीएम योगी बोले- किताबें देती हैं दुनिया समझने की ताकत

लखनऊ (एजेंसी)। लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में गोमती पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ हुआ। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोत्सव का उद्घाटन कर कहा कि डिजिटल युग में भी युवाओं का किताबों से जुड़ाव बना हुआ है। उन्होंने कहा कि युवा पढ़ना चाहते हैं, आवश्यकता सिर्फ किताबों को उन तक सुगमता से पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री योगी ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स पढ़ने की अपील भी की। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बढ़ती स्क्रीन टाइम पर चिंता व्यक्त कर कहा कि स्क्रीन हमें दुनिया दिखाती है, लेकिन पुस्तकें हमें दुनिया को समझने की वास्तविक शक्ति देती हैं। उन्होंने किताबों को ज्ञान, विचार, संस्कार और कल्पनाशक्ति विकसित करने का माध्यम बताया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। विरोध प्रदर्शन की आशंका के चलते समाजवादी छात्र सभा और एनएसयूआई के कुछ सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया। नौ दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में 121 प्रकाशक करीब 250 स्टॉलों पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अवधी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं की हजारों पुस्तकें उपलब्ध करा रहे हैं। 20 सितंबर तक चलने वाले पुस्तक महोत्सव में प्रवेश पूरी तरह निशुल्क है।

किसानों का अनोखा विरोध : सर्वेक्षकों को पेटीकोट पहनाकर लिपस्टिक लगा पूरे गांव में घुमाया

-सर्वे के नाम पर कथित अवैध वसूली से आक्रोशित थे किसान

महोबा (एजेंसी)। महोबा में फसल बर्बादी के सर्वे के नाम पर कथित अवैध वसूली से आक्रोशित किसानों ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए किसानों ने सर्वे करने पहुंचे कुछ लोगों को पकड़ा और उन्हें ब्लाउज-पेटीकोट पहनाकर, गले में जूतों की माला डालकर, लिपस्टिक लगा पूरे गांव में घुमाया। बाद में इन व्यक्तियों को पुलिस के हवाले किया। घटना के बाद, बीजेपी विधायक बृज भूषण राजपूत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दिया है। वायरल वीडियो में विधायक कथित तौर पर ग्रामीणों से वीडियो कॉल पर बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पैसे लेने वालों को पेटीकोट और चूड़ियां पहनाओ, लिपस्टिक लगाओ, गले में जूतों की माला डालकर मुंह काला करो व पूरे गांव में घुमाओ। उन्होंने पुलिस के हवाले करने से पहले उन्हें न मारने की सलाह दी। यह घटना तब हुई जब महोबा में बर्बाद हुई फसलों के नुकसान का सर्वे चल रहा था। इसी दौरान, किसानों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग सर्वे के नाम पर अवैध वसूली कर रहे थे। विधायक का वीडियो सामने आने के बाद उनकी भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यह दावा किया जा रहा है कि ग्रामीणों ने विधायक के निर्देशों पर ही यह कार्रवाई की। हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि और पूरे घटनाक्रम की पुलिस जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस द्वारा कथित अवैध वसूली के आरोपों की भी गहनता से जांच की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वास्तव में किसानों से पैसे मांगे गए थे या नहीं।

सर्पदंश के इलाज में भारतीय वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता

बेंगलुरु (एजेंसी)। भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने सर्पदंश के इलाज की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों ने ऐसा रीकॉम्बिनेंट एंटीवेनम विकसित किया है. जो भारत में पाये जाने वाले कई जहरीली कोबरा प्रजातियों के घातक विष को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह शोध ढ्ढढ्ढरू के वैज्ञानिकों ने टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क के सहयोग से किया है।

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस के सभी पदों से दिया इस्तीफा

मेरे ओएसडी रहे चंदन पर आरोप सही हैं तो मेरे शर्मिंदगी होगी

देहरादून, एजेंसी।
उत्तराखंड कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अचानक कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने यह बड़ा फैसला शनिवार को लिया है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके ओएसडी रहे चंदन सिंह जीना के ठिकानों पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में नकदी और सोना बरामद किया था।

रावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखकर अपने इस्तीफे की वजह बताई। उन्होंने कहा कि टीवी पर उनके सहयोगी के घर से भारी मात्रा में कैश और जूलरी मिलने की खबरें चल रही हैं, जिसकी सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी। रावत ने स्वीकार किया कि चंदन सिंह जीना उनके ओएसडी रहे हैं, और यदि ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा या ओएमआर शीट से छेड़छाड़ में उनके खिलाफ कोई गड़बड़ी या सबूत पाए जाते हैं, तो यह उनके लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। हालांकि, उन्होंने जीना पर लगे आरोपों पर अविश्वास भी जताया।

अपने इस्तीफे का कारण बताते हुए रावत ने कहा, उत्तराखंड के चुनाव में भारी स्टेक्स हैं। मुझसे जब भी कोई व्यक्ति पूछता था कि चुनाव कब हो रहे हैं? तो मैं हंसी में उनसे कहता था कि भई चुनाव तब होंगे, जब सीबीआई मेरे दरवाजे पर दस्तक देने आएगी। यदि अभी नहीं आई है तो इसका अर्थ है कि चुनाव अगले वर्ष मार्च-अप्रैल में ही होंगे। लेकिन इस बार मेरे घर पर नहीं, मेरे एक सहयोगी के घर पर दस्तक देकर एक नरेटिव बनाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में हरीश रावत के किसी भी कृत्य से यदि पार्टी के संघर्ष में कोई कमजोरी आती है, तो वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी सदस्यता और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कार्यसमिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य पद से विनम्रतापूर्वक हटने का निर्णय लिया है, ताकि उनकी वजह से पार्टी के संघर्ष में कोई कमजोरी न आए।

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इसका गठन राज्य के नौजवानों के भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया था। उन्होंने अपने कार्यकाल में पब्लिक सर्विस कमीशन को समय पर परीक्षाएँ लेने के लिए बाध्य किया और 42,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्तियां हुईं। उन्होंने स्वीकार किया कि यदि नियुक्तियों में कोई एरर ऑफ जजमेंट हुआ है, तो वह उत्तराखंड के लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यूकेएसएसएससी के चेयरमैन की नियुक्ति पिछली सेवा रिकॉर्ड और तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी की सलाह पर की गई थी, जिन्हें शिकायत मिलने के बाद उन्होंने ही हटाया था। रावत ने यह भी कहा कि कौन व्यक्ति कहां गलती कर दे, कोई नहीं जान सकता, ठीक वैसे ही जैसे किसी को नहीं पता होता कि आरएसएस का कोई पदाधिकारी भ्रष्ट निकल सकता है। चंदन सिंह जीना 2014 से 2017 तक हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके ओएसडी रहे थे। ईडी ने उनके आवास से 32 लाख रुपये नकद, 12 लग्जरी घड़ियां और 200 ग्राम सोना बरामद करने की जानकारी दी थी, ये बरामदगी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी की जांच के संबंध में हुई थी।

जोधपुर में गरजे जापानी फाइटर जेट-वीर गार्जियन युद्धाभ्यास का पाकिस्तानी कनेक्शन

जोधपुर(एजेंसी)। जोधपुर एयरबेस पर जापानी शक्तिशाली एफ-2ए फाइटर जेट पहुंच चुके हैं, जहाँ वे भारतीय वायुसेना के सुखोई-30एमकेआई विमानों के साथ संयुक्त हवाई युद्धाभ्यास वीर गार्जियन में हिस्सा ले रहे हैं। 9 से शुरू होकर 22 सितंबर तक चलने वाला अभ्यास हवा से हवा में मुकाबला, डॉगफाइट, रात्रि अभियान और हवा में ईंधन भरने जैसी जटिल तकनीकों पर केंद्रित है। इसका प्राथमिक लक्ष्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हवाई-समुद्री अभियानों में सहयोग बढ़ाना है, साथ ही पाकिस्तानी वायुसेना के एफ-16 फाइटर जेट्स से निपटने की भारतीय क्षमता को मजबूत करना महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस युद्धाभ्यास में जापान के एफ-2ए फाइटर जेट की भूमिका विशेष रूप से अहम है। मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज और अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन के सहयोग से विकसित यह विमान अमेरिकी एफ-16 के डिज़ाइन पर आधारित है, लेकिन जापान ने अपनी विशिष्ट समुद्री सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें पंखों, रडार और अन्य प्रणालियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। एफ-2ए फाइटर के साथ अभ्यास वायुसेना को एफ-16 जैसे विमानों से जुड़े खतरों का सामना करने का अमूल्य अनुभव प्रदान कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी अमेरिकी एफ-16 फाइटर फाल्कन विमानों का बेड़ा है। यह प्रशिक्षण भारतीय वायुसेना को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और राडार से चकमा देने की रणनीतियाँ विकसित करने में सीधी मदद करेगा। उल्लेखनीय है कि 27 फरवरी 2019 की बालाकोट एयरस्ट्राइक के दौरान भारतीय वायुसेना का सामना एफ-16 फाइटर जेट से हुआ था, जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने मिग-21 बाइसन से एक पाकिस्तानी एफ-16 जेट को मार गिराया था। वीर गार्जियन अभ्यास का यह दूसरा चरण है। इससे पहले जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना के चार एसयू-30एमकेआई विमानों ने जापान के हयाकुरी एयरबेस पर जापान के एफ-2 और एफ-15 लड़ाकू विमानों के साथ प्रशिक्षण लिया था।

बांग्लादेश में बिजली संकट का गहराया खतरा: अडानी प्लांट में गंभीर तकनीकी खराबी

कोलकाता, एजेंसी।
झारखंड स्थित अडानी पावर के गोड्डा अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल पावर प्लांट की एक 800 मेगावाट यूनिट में अचानक आई गंभीर तकनीकी खराबी ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय बिजली ग्रिड पर भारी दबाव डाल दिया है। इस अप्रत्याशित गड़बड़ी से बांग्लादेश को होने वाली बिजली आपूर्ति में बड़ी कटौती दर्ज की गई है, जिससे ढाका सहित देश के कई प्रमुख इलाकों में बड़े पैमाने पर लोड-शेडिंग का खतरा बन गया है। यह झटका तब आया है जब बांग्लादेश पहले से ही आर्थिक तंगी और ईंधन की कमी से जूझ रहा है, जहां पूरे देश में बिजली की मांग चरम पर है। अंतरिम सरकार के लिए स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है। बिजली अधिकारियों के अनुसार, अडानी पावर की यूनिट की मरम्मत और दोबारा ग्रिड से जोड़ने में कुछ समय लग सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच जारी बिजली आपूर्ति समझौते और बांग्लादेश के ऊर्जा संकट की चुनौतियां बढ़ गई हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, बांग्लादेश में 136 पावर प्लांट होने के बावजूद, कोयले, गैस और तेल की कमी के कारण मांग के मुताबिक बिजली पैदा करने में मुश्किल हो रही है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने के कारण कई प्लांट अक्सर बंद रहते हैं या अपनी क्षमता से कम पर चल रहे हैं। इस घटनाक्रम को लेकर बांग्लादेशी एक्सपर्ट्स गंभीर आरोप लगा रहे हैं।

अडानी पावर ने कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सूत्रों ने प्लांट की एक यूनिट में खराबी की पुष्टि की है और उम्मीद जाहिर की हैं कि 3-4 दिनों के भीतर ठीक किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, समस्या बॉयलर में आई है, इस ठीक करने का काम शुरू करने से पहले ठंडा होने में करीब 48 घंटे लग सकते हैं। इसके चलते बिजली उत्पादन को सामान्य होने में कई दिन लगने की संभावना है। यह जानकारी पावर ग्रिड कंपनी और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (बीपीडीबी) के सूत्रों ने दी है, जिन्होंने 2017 में अडानी पावर के साथ मुताबिक, बांग्लादेश में 136 पावर बिजली खरीद समझौता किया था।

लद्दाख में पदयात्रा के लिए वांगचुक ने सीजेपी से मांगी मदद

बोले- ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और अधिकारियों को निलंबित करने का रिकॉर्ड बनाऊंगा

नई दिल्ली, एजेंसी।
26 दिन तक अनशन करके जंतर-मंतर पर एक आंदोलन में जान फूंकने वाले सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अब उसी आंदोलन से जुड़े कॉकरोचों (अपने समर्थकों) से मदद मांगी है। उन्होंने अपनी पिछली भूख हड़ताल की याद दिलाते हुए लद्दाख में अपनी मुहिम के लिए साथ मांगा है। वांगचुक ने 19 से 24 सितंबर तक लद्दाख में एक पदयात्रा का ऐलान किया है और इसमें शामिल होने की अपील की है। आंदोलन के मुखिया अभिजीत दीपके ने वांगचुक के ट्वीट के कई घंटों बाद सकारात्मक प्रतिक्रिया तो दी, लेकिन यह साफ नहीं किया है कि वह या उनकी टीम इसमें शामिल होगी या नहीं।

लद्दाख में लोकतांत्रिक ढांचे की बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत के लिए दिल्ली आए सोनम वांगचुक ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि वह दिल्ली में उस जगह के बगल में हैं जहां उन्होंने उनके साथ कई हफ्ते भूखे रहकर बिताए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी प्रदर्शन या अनशन के लिए नहीं, बल्कि लद्दाख की

संस्कृति, प्रकृति और भूमि के संरक्षण के लिए गृह मंत्रालय के साथ चल रही बातचीत की कड़ी में यहां आए हैं। सरकार के साथ अपनी बैठक को लेकर सोनम वांगचुक ने निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बैठक में केवल चाय अच्छी थी और कोई नया कदम नहीं उठाया गया। वांगचुक के अनुसार, पुराने हो चुके फैसलों, जैसे लद्दाख में विधानसभा बनाने और उसे पूरा प्रशासन सौंपने की भावना का उल्लंघन करने की प्रक्रिया चल रही है, उसे रोकने का भी कोई आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि एलजी प्रशासन बहुत बड़े-बड़े फैसले लेने में लगा है, जिसके बाद लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वांगचुक ने कहा, हमने सरकार से छोटी सी आश्वासन की उम्मीद की थी कि जब तक लद्दाख में लोकतांत्रिक ढांचा न आ जाए, तब तक एलजी ऐसे बड़े फैसले न लें। हमें इसका इंतजार है।

सोनम वांगचुक ने अपने समर्थकों को लद्दाख में आयोजित होने वाली पांच दिवसीय पदयात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद के लिए आएं। हम लद्दाख में 19 से 24 सितंबर तक एक बड़ी पदयात्रा करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यदि उन्हें एक सप्ताह में सरकार से आवश्यक आश्वासन मिल जाता है, तो वे इसे शहीदों की याद में एक यादगार पदयात्रा के रूप में मनाएंगे, जिन्होंने लद्दाख के लिए अपनी जान दी। अन्यथा, इसे पूरे भारत की जनता की तरफ से एक बड़े प्रदर्शन में बदला जाएगा ताकि लद्दाख के साथ न्याय हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह केवल लद्दाख के लिए नहीं है, क्योंकि लद्दाख हिमालय का वह क्षेत्र है जहां से देश को पानी और साफ हवा मिलती है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों ने बिना वर्दी और वेतन के हर युद्ध में देश की रक्षा की है, और अब देश को लद्दाख की रक्षा में आगे आने की जरूरत है। सोनम वांगचुक की शुक्रवार शाम की अपील पर शनिवार सुबह अभिजीत दीपके ने एक शब्द में जवाब दिया। उन्होंने वांगचुक का वीडियो शेयर करते हुए केवल स्टैंड विद लद्दाख लिखा। हालांकि, इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वह या उनकी टीम लद्दाख में पांच दिवसीय पदयात्रा में शामिल होंगे या नहीं। खबर लिखे जाने तक दीपके के अलावा अन्य प्रमुख नेताओं ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी।

ब्रिक्स में अजमेर शरीफ के हाजी सलमान चिश्ती ने दिया एकता का संदेश

नई दिल्ली, एजेंसी।
राजधानी दिल्ली में 12 सितंबर से 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। इस महत्वपूर्ण मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे वैश्विक नेता एक साथ दिखाई दिए। इसी के मद्देनजर देशभर से कई धार्मिक नेताओं को भी इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। ब्रिक्स समिट में शिरकत करने आए अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने आपसी भाईचारे और सौहार्द को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कहीं।

हाजी सलमान चिश्ती ने एक बातचीत में कहा कि आज ब्रिक्स समिट के तहत पूरे भारत से आध्यात्मिक नेता यहां आए हैं। उन्होंने आपसी सौहार्द बनाए रखने को लेकर कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सदियों से यही संदेश रहा है कि सभी से प्यार करें और किसी से नफरत न करें। यह संदेश भारत की समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है,

जहां विभिन्न धर्मों के लोग सदियों से सद्भाव में रहते आए हैं। अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन ने अपने संबोधन में आगे कहा, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा संदेश है कि भारत की धरती पर पूरी दुनिया के लोग जुटे हैं। ब्रिक्स समिट हो रही है, दुनिया भर के नेता यहां हैं और आज संदेश बिल्कुल साफ है। कोई अन्याय नहीं। अन्याय का कोई स्थान नहीं है और भारत ने हमेशा न्याय, करुणा, दया और एकता के मूल्यों को बनाए रखा है। सलमान चिश्ती ने जोर देकर कहा कि पूरी दुनिया एक परिवार है और हम सब मिलकर सबकी सेवा कर रहे हैं। यह बात भारतीय दर्शन वसुधैव कुटुम्बकम् को दर्शाती है, जिसका अर्थ है पूरी पृथ्वी एक परिवार है। ईरानी दूतावास की तरफ से भारत के कई धार्मिक नेताओं को ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए बुलाया गया था। इस दौरान अजमेर शरीफ दरगाह के अलावा भी कई अन्य धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने भारत के धार्मिक नेताओं और बुद्धिजीवियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं भारत सरकार और प्रधानमंत्री की शानदार मेजबानी के लिए उनकी तारीफ करना चाहता हूं। हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई है और मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत और संबंध संस्कृति, टेक्नोलॉजी, व्यापार, विज्ञान, अर्थव्यवस्था और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग और आपसी समझ को बढ़ाने का रास्ता साफ करेंगे। यह सम्मेलन वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के साथ-साथ विभिन्न देशों और संस्कृतियों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देने का एक मंच बन गया।

सिंधु सीमा पर दीवारों पर आपत्तिजनक नारे और भित्तिचित्र बनाने के मामले में 3 गिरफ्तार

खालिस्तारी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक पोस्ट में इस कृत्य की ली थी जिम्मेदारी

नई दिल्ली, एजेंसी।
दिल्ली पुलिस ने आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के इशारे पर सिंधु बॉर्डर पर खालिस्तान समर्थक भित्तिचित्र बनाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली और हरियाणा राज्यों के बीच स्थित सिंधु सीमा पर दीवारों पर आपत्तिजनक नारे और भित्तिचित्र 6 सितंबर को बनाए गए थे। प्रतिबंधित समूह सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक्स पर एक पोस्ट में इस कृत्य की जिम्मेदारी ली थी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जांचकर्ताओं को सिंधु सीमा पर

लगे सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों के बारे में सुराग मिले, जिसके आधार पर पुलिस टीम ने तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों में से एक पन्नू के सीधे संपर्क में था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना तब हुई जब विदेशों में सक्रिय खालिस्तान समर्थक संगठनों ने आईएसआई के सीधे निर्देशों के तहत अपने परिचालन ढांचे में बदलाव किया और अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई से बचने के लिए हिंसक अपराध से ध्यान हटाकर राजनीतिक प्रचार की ओर किया। अब जब अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां खालिस्तान मुद्दे पर भारतीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं, तो इन समूहों ने अपने काम करने के तरीके को बदलने का फैसला किया है।

आइए, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों का एक साथ करते हैं ऑडिट

पायलट के सीजेपी को लेकर दिए बयान पर आप नेता सिसोदिया का चैलेंज

नई दिल्ली,, एजेंसी।
क्या कॉकरोच जनता पार्टी पक्षपाती हो गई है? क्या सीजेपी किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है, इसे देखकर मापदंड तय करती है? ये सवाल कांग्रेस के नवनियुक्त पंजाब प्रभारी सचिन पायलट के हमले के बाद उठने लगे हैं। सचिन पायलट ने कहा कि सीजेपी को आम आदमी पार्टी शासित पंजाब में स्कूलों की उसी साहस के साथ जांच करनी चाहिए, जिसके साथ वह अन्य राज?यों में करती है। पायलट के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी उनपर हमलावर हो गई है।

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सचिन पायलट को ही चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि वे पंजाब में 1000 शानदार स्कूल दिखा सकते हैं, क्या सचिन पायलट कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में ऐसे 1000 स्कूल दिखा सकते हैं? इस तरह चुनावी राज्य पंजाब में स्कूलों की गुणवत्ता पर राजनीति शुरू हो गई है। पायलट की यह टिप्पणी पंजाब के लुधियाना में सीजेपी द्वारा तीन स्कूलों के ऑडिट के बाद आई है। सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास के नेतृत्व में एक टीम ने इन स्कूलों का दौरा किया था। टीम ने एक सरकारी 'स्कूल ऑफ एमिनेंस', एक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। इसमें एक स्कूल में अच्छी सुविधाओं का उल्लेख किया गया, जबकि अन्य में कुछ कमियां मिली। आम आदमी पार्टी ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए कमियों को दूर करने की बात कही है।

पायलट ने पंजाब में स्कूलों के ऑडिट को लेकर आम आदमी पार्टी और सीजेपी पर निशाना साधा है। शुक्रवार को पायलट ने कहा कि पंजाब या देश के किसी भी हिस्से में स्कूलों का ऑडिट स्वागत योग्य है। उन्होंने मांग की कि पंजाब में भी ऑडिट उसी नजरिए, उन्हीं सवालों और उसी साहस के साथ किया जाना चाहिए, जिस तरह अन्य राज्यों की सरकारों का ऑडिट किया जाता है। पायलट ने कहा कि पंजाब किसी विशेष छूट का हकदार नहीं है और आप को भी किसी तरह की 'दोस्ताना छूट' नहीं मिलनी चाहिए।

आप नेता और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम ऐसे 1,000 बेहतरीन स्कूल दिखा सकते हैं। आइए, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों का एक साथ ऑडिट करते हैं। बोलिए! क्या आप यह चुनौती स्वीकार करते हैं?' बीजेपी शासित

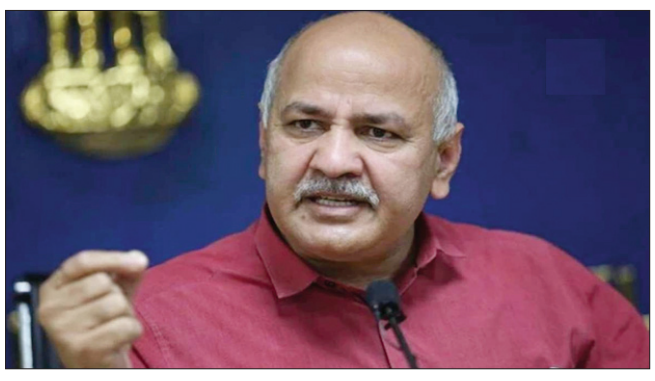

राजस्थान के जर्जर स्कूलों का पायलट द्वारा किए जा रहे बचाव पर सवाल उठाते हुए आप के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने पूछा कि आप इस रिश्ते को क्या नाम देते हैं? उन्होंने आगे कहा कि हम साथ जाकर इन स्कूलों का ऑडिट भी कर सकते हैं। बताइए, क्या आप इसके लिए तैयार हैं?